04 - संविधान संशोधन एक चतुराई भरा कदम

05 - क्या राज्यपाल धन विधेयकों को रोक सकता है?

A Daily News Magazine

भोपाल

सोमवार, 01 सितंबर, 2025

06 - श्री सांवरिया सेठ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ, निकली भव्य...

07 - सुरेश पचौरी की पत्नी के रिटायरमेंट पार्टी में दिखे कमलनाथ

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 04, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

भविष्य के कार्यक्रम के साथ वैचारिक कुहासे पर प्रहार

उमेश चतुर्वेदी

किसी संगठन की सौ साल की यात्रा सामान्य बात नहीं है। आने वाले दशहरे को संघ अपनी स्थापना के सौ साल पूरे कर लेगा। चौतरफा कटु वैचारिक हमले, आरोप-प्रत्यारोप के बीच से निकलते हुए सौ साल की यात्रा पूरी कर लेना कोई हंसी-खेल नहीं है। अपने स्वयंसेवकों के त्याग, उनकी कठोर मेहनत और पैरों को गहरे तक छेद देने वाले कांटों के बीच से राह बनाने की उनकी कोशिशों की वजह से संघ उस दौर से निकल आया है, जिसमें किसी नव संगठन को उपेक्षा और विरोध के कड़वे दंश को झेलना पड़ता है।

जिस समय आरएसएस की स्थापना हुई, ठीक उसी वक्त देश में कम्युनिस्ट आंदोलन भी शुरू हुआ। बेशक आजादी के तत्काल बाद कम्युनिस्ट आंदोलन को कुछ राजनीतिक सफलताएं जरूर मिलीं, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो आज संघ के मुकाबले उसकी सफलता कहीं पीछे दिखती है। भारतीय वैचारिकी और सांस्कृतिक सोच की बुनियाद पर स्थापित संघ का विस्तार विदेशी धरती तक हो चुका है। बेशक उसके कार्यकर्ता विदेशों में संघ के नाम पर काम न कर रहे हों, लेकिन उनके दिल में संघ का दर्शन और विचार ही है। संघ का यह दावा नहीं है कि उसका भारतीय जनता पार्टी पर नियंत्रण है, वह कहता है कि उसके कार्यकर्ता भाजपा में जरूर हैं। लेकिन यह सर्वमान्य तथ्य है कि बीजेपी की बुनियादी सोच और राजनीतिक दर्शन की बुनियाद संघ की वैचारिकी ही है। बीते स्वाधीनता दिवस को प्रधानमंत्री मोदी लालकिले की प्राचीर से अपने पारंपरिक संबोधन में संघ की सौ साल की यात्रा और उसकी वैचारिकी को याद करके एक तरह से अपने संबंधों और संघ की सोच की महत्ता की मुनादी कर चुके हैं।

अपने सौ साल की यात्रा में संघ ने जीवन के हर मुमकिन क्षेत्रों में काम किया है और विराट स्तर पर उसके काम को मान्यता भी मिली है। सौ साल की यात्रा के बाद हर संगठन के सामने आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट दिशा नीति और दर्शन की जरूरत है। संघ प्रमुख के तीन दिनों के व्याख्यान की एक वजह इसी दर्शन को आम लोगों से साझा करने और अपने कार्यकर्ताओं तक उसकी गहन पहुंच बाने की कोशिश कहा जा सकता है। 'सौ वर्ष की संघ यात्रा, नए क्षितिज' विषय पर राजधानी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहनराव भागवत के व्याख्यान को सावन की मेह कहा जा सकता है, जिसने संघ की वैचारिकी पर छाए आग्रही कुहासे को छांटने की सफल कोशिश तो की ही, संघ के कार्यकर्ताओं को अगले सौ साल के लिए आगे बढ़ते रहने के लिए दिशा भी दी। संघ के हिंदुत्व को अक्सर संकीर्ण नजरिए से देखा जाता है। संघ प्रमुख ने इसे खारिज करते हुए कहा कि संघ के हिंदुत्व का मतलब वसुधैव कुटुंबकम है। संघ के हिंदू राष्ट्र का मतलब यह नहीं कि राष्ट्र में गैर हिंदू नहीं होंगे, बल्कि वह ऐसा राष्ट्र होगा, जहां पंथ, संप्रदाय या भाषा के नाम पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा, सबके साथ बराबरी का व्यवहार और न्याय होगा। संघ बार-बार कहता है कि उसका राष्ट्र, आधुनिक नेशन की तरह नहीं है, जिसमें स्टेट यानी राज भी शामिल है। संघ प्रमुख ने इस बार भी इसे दोहराया। उनका कहना था कि संघ का उद्देश्य मानव का निर्माण है, जो व्यक्ति, समाज, विश्व और सृष्टि को साथ लेकर चले, राष्ट्र को मजबूत बनाए और राष्ट्र निर्माण में अपना पूर्ण योगदान करे।

बीते कुछ वर्षों से हिंदू और हिंदुत्व को संकुचित अर्थों में लिया जाता रहा है। संघ प्रमुख ने इस संदर्भ में कहा कि हिंदू की चर्चा का मतलब राष्ट्रनिष्ठ जिम्मेदारी का बोध है । इतिहास में 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को प्रस्थान बिंदु के रूप में याद करते हुए भागवत ने नया दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने कहा कि भले ही इस संग्राम में भारतीयों को असफलता मिली, लेकिन उसके बाद लोगों में अपनी स्वाधीनता को लेकर विचार बना। इसके बाद चार तरह की वैचारिक धाराएं उभरीं, स्वाधीनता प्राप्ति के लिए राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस के रूप में सामने आई। मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस से ही आज की राजनीतिक पार्टियां एक तरह से निकली हुई हैं। उन्होंने कहा कि 1857 के बाद आजादी के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। ये क्रांतिकारी लोग थे। कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्हें लगा कि हमारे समाज में कई बुराइयां हैं, उन्हें दूर करने के लिए उन्होंने समाज सुधार आंदोलन शुरू किया, तो एक धारा ऐसी भी रही, जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार पर जोर दिया। इस श्रेणी में दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का नाम लिया जा सकता है। भागवत के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इन चारों धाराओं के साथ काम करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिन्हें हम हिंदू के नाम से जानते हैं, उन्हें संगठित करना जरूरी है और संघ की स्थापना हुई। नेता, नीति, पार्टी, विचार और संगठन की बजाय हर व्यक्ति को सक्षम होना होगा। संघ की वैचारिकी इसी सोच पर केंद्रित होकर व्यक्ति निर्माण के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रही है।

इसके साथ ही संघ ने आगे के लिए पंच परिवर्तन के सिद्धांत स्वीकार रखा है और इन्हीं बिंदुओं पर समाज के बीच काम कर रहा है। संघ प्रमुख ने अपने व्याख्यान में इसको विस्तार से समझाकर एक तरह से आने वाले दिनों का संघ का कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया। इस पंच परिवर्तन का पहला बिंदु है, ससामाजिक समरसता। इसके तहत संघ और उसके असंख्य कार्यकर्ता लगातार समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द्र और प्रेम बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं। संघ के पंच परिवर्तन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कुटुम्ब प्रबोधन, जिसके तहत संघ की कोशिश राष्ट्र के विकास में परिवार को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इकाई के रूप में संवर्धित करने के प्रयासों में लगातार जुटा है। पंच परिवर्तन के तीसरे बिंदु पर्यावरण संरक्षण के तरह संघ पृथ्वी को माता तो मानता ही, इसी आधार पर पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार सक्रिय रहता है और अपने स्वयंसेवकों के साथ ही समाज से ही आशा करता है कि वह भी ऐसा ही करे। पंच परिवर्तन के चौथे बिंदु स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के तहत संघ अपने विभिन्न सहयोगी संगठनों और प्रकल्पों के माध्यम से देश की स्वदेशी अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहा है। पंच परिवर्तन के पांचवें बिंदु नागरिक कर्तव्य के तहत संघ की कोशिश देश के हर नागरिक की वैचारिकी को इस तरह स्थापित करना है कि वह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रहित में अपना अप्रतिम योगदान दे सके।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

1018 गांवों में बाढ़, पंजाब में 'जल तांडव'

- हिमाचल में भी जारी है कहर
- रोकी गई मणिमहेश यात्रा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पंजाब के आठ जिलों में भारी बारिश के बाद 1018 गांवों में बाढ़ की स्थिति है। बाढ़-बारिश में अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग लापता हैं। 11 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के घोनेवाले में धुस्सी बांध टूट गया। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अजनाला शहर तक पहुंच गया। बाढ़

की वजह से 80 गांव पानी में डूबे हैं। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के बदर गांव में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। वहीं, रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक महिला लापता है। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा 6 दिन से रुकी है।

राजस्थान के गंगानगर में किले की दीवार ढही

राजस्थान के हनुमानगढ़ में बाढ़ की आशंका के कारण हेल्थ डिपार्टमेंट और अन्य विभागों ने कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी। यहां मकान ढह गया, किले की दीवार गिर गई। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के बदर गांव में शनिवार सुबह लैंडस्लाइड हुई। मलबे से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं। वहीं, रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई। एक महिला लापता है। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा 6 दिन से रुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से 18 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अब तक 774 मकान बारिश में ढह चुके हैं। बलिया में गंगा किनारे तेजी से कटान हो रहा है। इसके चलते 24 घंटों में चक्की नौरंगा और भगवानपुर क्षेत्र के 24 मकान गंगा में समा गए। पंजाब में इस समय सतलुज, ब्यास और रावी नदियां अपने उफान पर हैं।

मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मांगा चीन का साथ

पीएम ने चीनी राष्ट्रपति को भारत आने का दिया न्योता

बीजिंग (एजेंसी)। सात साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच 50 मिनट बातचीत हुई। इसमें मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी ने आतंकवाद को वैश्विक मुद्दा बताया और इसके खिलाफ लड़ाई में साथ देने की मांग की। मोदी ने ये भी कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और यह पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जिनपिंग को भारत में आयोजित ब्रिक्स 2026 में आने के लिए न्योता दिया। वहीं, मीटिंग में जिनपिंग ने कहा कि पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई। ड्रैगन (चीन) और हाथी (भारत) को साथ आना चाहिए। मोदी ने बातचीत के दौरान कहा-पिछले साल कजान में हमारी बहुत उपयोगी चर्चा हुई थी, जिससे हमारे संबंध बेहतर हुए। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद, शांति और स्थिरता का माहौल बना है। सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

जिनपिंग बोले- चीन और भारत दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है

जिनपिंग ने पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत में कहा कि चीन और भारत दुश्मन नहीं, बल्कि साझेदार हैं और दोनों देश एक-दूसरे के लिए खतरा नहीं विकास के लिए अवसर हैं। जिनपिंग ने कहा कि जब तक दोनों देश अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में काम करते रहेंगे तब तक हम विकास करते रहेंगे।

पीएम मोदी बोले-दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों को होगा फायदा

इससे पहले पीएम मोदी ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताते हुए कहा, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई थी। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद,

शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। सीमा मुद्दे पर हमारे विशेष प्रतिनिधियों ने समझौता किया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

औद्योगिक और ऊर्जा क्रांति का आधार बनेगी नई हाइड्रोजन निर्माण इकाई : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने मुरैना के औद्योगिक क्षेत्र पिपरसेवा में ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण इकाई का किया भूमि-पूजन

भोपाल/ग्वालियर (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मुरैना के पिपरसेवा में हो रहा हाईड्रोजन निर्माण इकाई का भूमिपूजन नई औद्योगिक क्रांति, नई ऊर्जा क्रांति और नए मध्यप्रदेश की नींव है। मुरैना की ऐतिहासिक धरती पर स्थापित हो रही यह इकाई ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की नई विकास यात्रा का प्रतीक बनेगी। चंबल की भूमि उपजाऊ और कमाऊ होने के साथ ही टिकाऊ भी है। मुरैना जो कभी बीहड़ों के कारण जाना जाता था, आज विकास और प्रगति की नई पहचान बना रहा है। मुरैना अब सिर्फ कृषि प्रधान जिला नहीं रहा बल्कि औद्योगिक हब के रूप में भी उभर रहा है। मुरैना की गजक ग्लोबली ट्रेंड हो रही है। देश की संसद के पुराने भवन का डिजाइन भी मुरैना के मितावली मंदिर से लिया गया था।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को मुरैना जिले के पिपरसेवा में जीएचटू सोलर लिमिटेड की हाईड्रोजन निर्माण इकाई के भूमि-पूजन अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उद्योगपतियों से संवाद कर आशय-पत्र भी वितरित किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया में एक नए आत्मविश्वास और क्षमता के साथ उभर रहा है। जी20 की सफल अध्यक्षता हो, इंडिया-मीडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर जैसी ऐतिहासिक पहल हो या यूनाईटेड किंगडम के साथ हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हर जगह भारत केवल सहभागी नहीं बल्कि मार्गदर्शक राष्ट्र के रूप में खड़ा है। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से तीसरे स्थान की ओर अग्रसर हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने भारत को 21वीं सदी की वैश्विक विकास यात्रा का इंजन बना दिया।

देश को ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज जैसी अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ेगी यह इकाई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किसानों, गरीबों और लघु उद्यमियों के लिए स्वदेशी की लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य सरकार और प्रदेशवासी पूरी प्रतिबद्धता से उनके साथ हैं। मुरैना में आरंभ हो रही हाईड्रोजन इकाई में कोरिया और ब्रिटेन की अग्रणी कम्पनियां तकनीकी सहयोग कर रही हैं। निकट भविष्य में इससे ग्रीन हाईड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। परियोजना से लगभग 500 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, साथ ही रोजगार के कई अप्रत्यक्ष अवसर भी सृजित होंगे। सात एकड़ भूमि पर बनने वाली यह परियोजना पूरे देश को ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी एनर्जी स्टोरेज जैसी अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ेगी।

मुख्यमंत्री करेंगे विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण व ऐप लोकार्पण

भोपाल। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण एवं ऐप का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 1 सितम्बर को मुख्यमंत्री निवास पर करेंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार श्रीराम तिवारी ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रातः 9:00 बजे शौर्य स्मारक पर कॉलेज, विश्वविद्यालय के युवाजन एवं छात्र-छात्राएँ एकत्रित होंगे। शौर्य स्मारक से बाइक रैली आरंभ होगी जो रवींद्र भवन तक जायेगी। रवींद्र भवन से बाइक रैली पैदल मार्च में बदलकर मुख्यमंत्री निवास के द्वार तक पहुँचेगी। इस अवसर पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ीः भारत के समय की पुर्नस्थापना की पहल विषय युवा संवाद कार्यक्रम भी होगा। जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव युवाओं से संवाद करेंगे।

साथ ही युवा संवाद में युवाओं से बात भी करेंगे

संस्कृति सलाहकार तिवारी ने बताया कि विक्रमादित्य वैदिक घडी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है। भारतीय काल गणना सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति का पुनरस्थापन विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप मंक उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 29 फरवरी 2024 को किया गया था। जिसे देश और दुनिया में अच्छा प्रतिसाद मिला।

श्रीराम तिवारी
संस्कृति सलाहकार

उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय परंपरा, वैदिक गणना और वैज्ञानिक दृष्टि का अद्भुत संगम है। यह स्वदेशी जागरण की महत्वपूर्ण कोशिश है, जो भारत को विश्व मंच पर मजबूती प्रदान करेगी।

तिवारी ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप की विशेषताएं बताते हुए कहा कि इस ऐप में 3179 विक्रम पूर्व (श्रीकृष्ण के जन्म), महाभारतकाल से लेकर 7000 से अधिक वर्षों के पंचांग, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, मास, व्रत एवं त्यौहार आदि की दुर्लभ जानकारियों को समाहित किया गया है। धार्मिक कार्यों, व्रत और साधना के लिए 30 अलग-अलग शुभाशुभ मुहूर्तों की जानकारी एवं अलार्म की सुविधा भी है। प्रचलित समय में वैदिक समय (30 घंटे), वर्तमान मुहूर्त स्थान, जीएमटी और आईएसटी समय, तापमान, हवा की गति, आर्द्रता आदि मौसम संबंधी सूचनाएँ भी लोगों को उपलब्ध करायी जा रही है। यह ऐप 189 से अधिक वैश्विक भाषाओं में उपलब्ध है। जिसमें दैनिक सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना तथा उसी आधार पर हर दिन के 30 मुहूर्तों का सटीक विवरण सम्मिलित है।

प्रेस वार्ता को विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के अन्वेषणकर्ता आरोह श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा भी उपस्थित थे।

सुप्रभात

इन आंखों को ख्वाब
दिखाकर लौट गये
बादल आये घूम
घुमाकर लौट गये
एक तुम्हारा ही तो
बहुत भरोसा था
तुम भी केवल बात
बनाकर लौट गये
उनका भी तो मुझ
पर है एहसान बहुत
जो आंसू पलकों तक
आकर लौट गये
कुछ ने दु:ख पूछा मेरा,
कुछ ऐसे थे
दरवाजे तक आये
आकर लौट गये
जो केवल एहसान
जताने आये थे,
वो केवल एहसान
जताकर लौट गये
अपने दिल का हाल
तुम्हीं से कहना था
तुम अपने अरमान
बुझा कर लौट गये
सावन आए बरसे
हम पर कुछ लम्हा
फिर प्रेमिल एहसास
थमाकर लौट गये।

– दिव्या सिंह सिसोदिया

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c

न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 01 सितंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

प्राइवेट अस्पतालों में नहीं हो रहा गरीबों का फ्री इलाज !

केंद्र-राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने थमाया नोटिस,मांगा जवाब

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दी है, जिसमें सरकारी जमीन पर बने या सरकारी रियायतों के आधार पर बने निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को फ्री इलाज का मामला उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुआई वाली बेंच ने 29 अगस्त को इस मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। यह याचिका मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर प्रसिद्ध एक्टिविस्ट संदीप पांडेय ने दाखिल की है। याचिका में यह मुद्दा उठाया गया है कि ऐसे निजी है अस्पतालों को सार्वजनिक जमीन

रियायती दरों पर इस शर्त पर दी गई थी कि वे गरीब श्रेणी के रोगियों को फ्री इलाज की सुविधा देंगे, लेकिन उन्होंने शर्तों का पालन नहीं किया। पीआईएल में कहा गया है कि राज्यों में लगातार ऑडिट रिपोर्ट, अदालत-निगरानी वाली जांचें और सरकारी अधिसूचनाएं यह दर्शाती रही हैं कि अस्पताल निर्धारित फ्री इलाज प्रतिशत (आमतौर पर 10 फीसदी इन पेशेंट बेड और 25 फीसदी आउट पेशेंट परामर्श) का पालन करने में लगातार असफल रहे हैं। यह सवाल उठाया गया है कि दिल्ली में कई अस्पतालों को शर्त थी कि वे अपने एक-तिहाई बिस्तर फ्री इलाज के लिए आरक्षित रखें।

अमेरिकी टैरिफ से पंजाब को 30 हजार करोड़ का नुकसान

- 8,000 करोड़ रुपए तो केवल कपड़ा निर्यात पर होगा नुकसान

चंडीगढ़ (एजेंसी)। अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ वॉर से पंजाब की इंडस्ट्री को 30 हजार करोड़ का नुकसान होगा। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। कई इंडस्ट्रियलिस्ट के ऑर्डर रुक गए हैं। टैरिफ के कारण पंजाब के 7 इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही अकेले 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान है। इनमें कपड़ा, मशीन टूल्स, फास्टनर्स, ऑटो पार्ट्स, खेल और लेदर, खेती उपकरण इंडस्ट्री शामिल है। इन उद्योगों से जुड़े उद्योगपतियों ने कहा कि अमेरिका के भारत पर बढ़ाए टैरिफ का फायदा पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन को होगा।

मोदी सरकार एचएएल से खरीदेगी 97 नए फाइटर जेट

- वायुसेना को सितंबर में मिल सकते हैं 2 तेजस मार्क-1ए

नई दिल्ली (एजेंसी)। रक्षा सचिव आरके सिंह ने शनिवार को कहा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सितंबर में भारतीय वायुसेना को दो तेजस मार्क-1ए लड़ाकू विमान सौंप सकता है। इन विमानों में वेपंस इंटीग्रेशन यानी हथियारों को जोड़ा भी किया गया है। इसके अलावा सिंह ने बताया, सरकार एचएएल के साथ 97 और तेजस खरीदने का नया करार करने जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 67,000

करोड़ रुपए होगी। फिलहाल 38 तेजस वायुसेना में शामिल हैं। इससे पहले न्यूज एजेंसी ने रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया था कि केंद्र सरकार ने 19 अगस्त को भारतीय वायुसेना के लिए 97 एलसीए मार्क 1ए फाइटर जेट खरीदने के लिए 62 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। दरअसल, फरवरी 2021 में सरकार ने एचएएल के साथ 83 तेजस मार्क-1ए खरीदने के लिए 48,000 करोड़ का करार किया था, लेकिन एक अमेरिकी इंजन की डिलीवरी में देरी की वजह से अभी तक एक भी एयरक्राफ्ट नहीं सौंप पाया। हालांकि, अब उम्मीद है कि 2028 तक सभी एयरक्राफ्ट्स वायुसेना को सौंप देगा। एलसीए मार्क 1ए, तेजस एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है। इसमें अपग्रेडेड एवियॉनिक्स और रडार सिस्टम लगे हैं। एलसीए मार्क-1ए के 65 फीसदी से ज्यादा उपकरण भारत में बने हैं। तेजस को भी हाल ने डेवलप किया है। यह सिंगल इंजन वाला हल्का लड़ाकू विमान है।

आवारा कुत्तों ने मुझे दुनियाभर में किया फेमस

- जस्टिस विक्रम नाथ बोले- उनकी भी दुआएं मिल रहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने शनिवार को कहा- मैं लंबे समय से कानून जगत में अपने छोटे-मोटे कामों के लिए जाना जाता था। मैं आवारा कुत्तों का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे न केवल देश में बल्कि दुनियाभर में फेमस कर दिया। केरल के तिरुवनंतपुरम में नेशनल लीगल सर्विस

अथॉरिटी की तरफ से आयोजित मानव-वन्यजीव संघर्ष पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन में बोलते हुए जस्टिस नाथ ने कहा कि वह भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई को भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने यह केस उन्हें सौंपा। दरअसल, 22 अगस्त को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है, वहीं वापस छोड़ दिया जाए। ये आदेश दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होगा। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा- इसके लिए नेशनल लेवल पर पॉलिसी बननी चाहिए। हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। देश के बाकी हाईकोर्ट में जहां भी मामले लंबित हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाए।

कमरे में पत्नी का, पेड़ पर पति का शव मिला

मृतक के पिता ने कहा- बेटे ने बहू का गला दबाया, फिर बाहर जाकर आत्महत्या कर ली

दमोह (नप्र)। दमोह जिले के आंजनी की टपरिया गांव में शनिवार रात करीब 3 बजे दंपती में हुए विवाद के बाद पत्नी कमरे में मृत मिली और पति का शव घर के पास पेड़ पर फांसी के फंदे पर मिला। आशंका जताई जा रही है कि पत्नी की हत्या के बाद पति ने आत्महत्या कर ली। बटियागढ़ थाना पुलिस के मुताबिक, 30 वर्षीय मृतक विजय लोधी के पिता देव सिंह लोधी ने बताया- शनिवार रात मैं, पत्नी, बेटा और बहू चारों ने खाना खाया। मैं और मेरी पत्नी अपने कमरे में सोने चले गए। बाजू के घर में बेटा और बहू चंदा चले गए। रात करीब 3 बजे बहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं उठा। दोनों को आवाज़ लगाई। घर की छज्जा पर जाकर देखा तो बेटा बहू का गला दबा रहा था। मैंने बेटे को चिल्लाया, लेकिन वह नहीं माना। जैसे-तैसे मैं दरवाजा तोड़कर घर में घुसा। बहू मृत अवस्था में पड़ी थी। बेटा वहां से भागने लगा। मैंने उसे पकड़ा तो उसने कहा कि मुझे मरना है। इसी बीच मैंने अपनी पत्नी से पड़ोसी को बुलाने के लिए कहा। जब तक मेरा पड़ोसी आया, मेरा बेटा मुझे धक्का देकर भाग निकला। मैं और मेरा पड़ोसी टॉर्च लेकर घर के पीछे गए तो वहां मेरा बेटा विजय पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। उसकी भी मौत हो गई।

गणेशोत्सव पर सुंदरकांड

भोपाल। नीलबढ़ स्थित सिद्धिविनायक-तिरुपति कालोनी में गणेशोत्सव के चौथे दिन शनिवार को सुंदरकांड का आयोजन किया गया। जिसमें सभी कालोनीवासियों ने श्रीगणेश वंदना के बाद सुंदरकांड का आयोजन किया। जिसमें सभी रहवासियों ने धर्मलाभ प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण किया।

नीमच के गांव में घुसा मगरमच्छ; दो घायल

वन विभाग की टीम ने देरी से रेस्क्यू किया ; ग्रामीणों ने खुद पकड़ा मगरमच्छ

नीमच (नप्र)। नीमच जिले के हनुमंतिया रावजी गांव में एक मादा मगरमच्छ ने दहशत फैला दी। रविवार सुबह 4 बजे गांव में मगरमच्छ दिखने के बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग को सूचना दी। पुलिस तत्काल पहुंची, लेकिन वन विभाग की टीम को आने में 5 घंटे लग गए।

वन विभाग की टीम के पास मगरमच्छ को पकड़ने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं थे। बिना पिंजरे और सुरक्षा सामग्री के रेस्क्यू शुरू किया गया। इस दौरान मगरमच्छ गांव की तरफ भागा। भगदड़ में मगरमच्छ ने मोहनलाल सुधार समेत एक अन्य ग्रामीण को घायल कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। वन विभाग की लापरवाही के बाद युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर मगरमच्छ को काबू किया।

गांधी सागर जलाशय में छोड़ा- मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंच गए थे। बेकाबू मगरमच्छ को काबू कर

लिया गया है। वन विभाग की टीम ने बाद में मगरमच्छ को गांधीसागर जलाशय में छोड़ दिया है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और वन्यजीवों का खतरा बढ़ गया है।

ठिकाना तलाश रहा था मगरमच्छ- नीमच डीएफओ, एसके अटोदे ने बताया है कि सुबह करीब 7 बजे सरपंच ने गांव में मगरमच्छ होने की सूचना दी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पहुंची। मगरमच्छ जलीय जीव होने के कारण अपने लिए ठिकाना तलाश रहा था। इस दौरान गांव में भगदड़ मंच गई। मगरमच्छ पकड़ने में जो उपकरण की जरूरत होती है। वह कर्मचारियों के पास थे।

मनोज जरांगे का भूख हड़ताल और ज्यादा तेज करने का ऐलान

- मराठा आरक्षण आंदोलनकारी ने कहा-पानी भी नहीं पिएंगे

मुंबई (एजेंसी)। मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे पाटिल ने आक्रामक रुख अपनाया है। वह ओबीसी कोटे से मराठा आरक्षण दिए जाने की मांग पर अड़े हैं। इसके लिए मराठों ने मुंबई के आजाद मैदान में एल्गार का आह्वान किया है। आज मनोज जरांगे पाटिल इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं और अब और भी आक्रामक हो गए हैं। गुरुवार से भूख हड़ताल शुरू हो गई है।

रविवार को भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। आज उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गईं तो भूख हड़ताल और भी कड़ा कर दिया जाएगा। जरांगे ने कहा है कि वह कल से पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे ने कहा कि कल यानी सोमवार से भूख हड़ताल और भी कड़ा कर दिया जाएगा। कल और आज मैंने पानी पिया, लेकिन सोमवार से मैं पानी नहीं लूंगा। मैं पानी पीना बंद कर दूंगा। सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए मैं भूख हड़ताल और भी कड़ा करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने मराठों से अपील करते हुए कहा कि मराठा युवा ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनका सिर झुक जाए। सभी को शांत रहना चाहिए। उन्हें कोई भी अन्याय या अत्याचार करने दें। जरांगे ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि वह बिना आरक्षण लिए मुंबई नहीं छोड़ेंगे। जरांगे ने यह भी कहा कि अगर किसी को रेनकोट या छाता चाहिए, तो एक भी रुपया न दें। कुछ लोगों ने व्यवसाय शुरू कर दिया है। वे समाज के नाम पर कमाई कर रहे हैं। रेनकोट बांटने के नाम पर पैसा जमा न करें। मैं यह आखिरी बार कह रहा हूं। महाराष्ट्र में मराठा किसी को पैसा नहीं देना चाहते। केवल गरीबों की सेवा करना चाहते हैं।

इंदौर आ रही फ्लाइट लौटी नई दिल्ली में सेफ लैंडिंग

- एयरलाइन बोली-पायलट को इंजन में फायर इंडीकेशन मिला था; 90 यात्री सवार थे

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली से इंदौर पर जा रही एअर इंडिया की फ्लाइट एआई 2913 (ए-320 नियो विमान) को दिल्ली लौटा लिया गया। पायलट को दाहिने इंजन में आग लगने की सूचना मिली थी। एअर इंडिया ने कहा- रविवार सुबह 6.15 बजे 90 यात्रियों के साथ प्लेन ने उड़ान भरी थी। करीब आधे घंटे बाद इंजन में फायर इंडिकेशन मिला। स्टैंडर्ड प्रोसेस के तहत पायलट ने इंजन बंद किया। बाद में प्लेन की एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग हुई। एयरलाइन ने कहा कि प्लेन का ग्राउंड इंस्पेक्शन कराया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को भी घटना की जानकारी दी गई है। 29 अगस्त को भी दिल्ली से श्रीनगर आ रही स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। अधिकारियों ने बताया था कि फ्लाइट एआई 385 में

प्रेशराइजेशन की समस्या के कारण दोपहर 3.27 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया था। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कॉकपिट क्रू ने उड़ान भरने के तुरंत बाद दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत देखा। मानक सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, चालक दल ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया और विमान को वापस दिल्ली ले गया। एयरलाइन ने पुष्टि की कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा, 31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरने वाली एआई 2913, उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौट आई, क्योंकि कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए, कॉकपिट क्रू ने इंजन बंद करने का फैसला किया और दिल्ली लौट आए, जहां विमान सुरक्षित रूप से उतरा। विमान को चेकिंग के लिए रोक दिया गया है, जबकि यात्रियों को इंदौर पहुंचाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई है।

पटना में 'गांधी से अंबेडकर' थीम पर निकलेगी यात्रा

- राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जारी हुआ रूट मैप

पटना (एजेंसी)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' रविवार की देर शाम पटना पहुंच गई है। इसके अगले दिन यानी सोमवार 1 सितंबर को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पटना में पैदल मार्च के रूप में निकाली जाएगी। यह पैदल यात्रा गांधी से अंबेडकर थीम पर निकाली जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ गांधी मैदान से होगा और समापन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पार्क में किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी को ओर से सोमवार को होने वाले मार्च का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक- राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेता सुबह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जुटेंगे। यहां 10.50 बजे 11.05 बजे तक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके

बाद सुबह 11.15 बजे यहां से पैदल मार्च के रूप में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी, जो अंबेडकर पार्क तक जाएगी। गांधी मैदान से शुरू होकर वोटर यात्रा का मार्च दोपहर 12.30 बजे अंबेडकर पार्क पहुंचेगा। यहां राहुल गांधी- तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य सहित महागठबंधन के नेता बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 12.40 से 2.30 बजे के बीच राहुल गांधी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

केरल में पहली बार सियासत के सेंटर पॉइंट बन रहे हिंदू

वाम सरकार करा रही अयप्पा सम्मेलन, 20 सितंबर से सबरीमाला मंदिर में आयोजन

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। समय कम है, इसलिए राजनीतिक दलों ने अपने 'सियासी मैदान और चुनावी हथियार' तैयार करने शुरू कर दिए हैं। बड़ी बात है कि इन मैदानों के केंद्र में पहली बार 'हिंदू' ज्यादा नजर आ रहे हैं। केरल में वामदल सीपीआई (एम) की सरकार है, जिसे नास्तिक भी माना जाता है। लेकिन, यही दल इस बार भगवान अय्यपा का 'आह्वान' करने जा रही है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 20 सितंबर से सबरीमाला की तलहटी में बसे पंपा में तीन दिवसीय ग्लोबल अयप्पा संगमम का आयोजन किया है। इसमें केरल के सभी पंथों के हिंदू संतों, उच्च ब्राह्मणों समेत सभी जाति वर्गों को आमंत्रित किया जा रहा है। भगवान अयप्पा के नाम पर इतना बड़ा आयोजन इसलिए भी चौंका रहा है, क्योंकि निचली जाति के

हिंदू और ओबीसी वोट हमेशा से सीपीआईएम को समर्थन देते हैं, लेकिन इस बार वाम दल की कोशिश उच्च जाति के हिंदुओं को साथ लाने की है।

भगवान अयप्पा चुनाव में बहुत अहम

भगवान अयप्पा का न केवल केरल के वोटर्स पर, बल्कि अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भी काफी प्रभाव है और सबरीमाला इन्हीं देवता का एकांतवास है। हर साल देश भर के लाखों हिंदू यहां दर्शन को पहुंचते हैं। इसलिए भगवान अयप्पा चुनाव में बहुत अहम हो गए हैं। हालांकि इस सीपीआईएम की इस कोशिश से केरल में मुख्य विपक्षी कांग्रेस नाराज हो गई है। केरल के मंदिर मामलों के विशेषज्ञ टीएस श्यामकुमार का कहना है कि पहली बार सीपीआईएम 'सुधारवादियों' को उकसाए बिना अयप्पा के भक्तों का विश्वास दोबारा जीतना चाहती है। वो अपने अल्पसंख्यक अनुयायियों के समर्थन को खोए बिना अयप्पा पूजा से जुड़ने का प्रयास कर रही है।

लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, बिल्डिंग उड़ी

फैक्ट्री मालिक-पत्नी समेत 4 की मौत,पड़ोसियों के घर टूटे

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में रविवार सुबह धमाका हो गया। हादसे में फैक्ट्री मालिक और उसकी पत्नी समेत 4 की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि, धमाके के बाद पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे के नीचे दबे हैं। डीएम-कमिश्नर मौके पर पहुंच गए हैं। पुलिस टीमें मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के 2-3 मकान भी टूट गए। इससे करीब 10 लोग घायल हुए हैं। मौके पर अफरा-तफरी का माहौल है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही घायलों को स्थानीय लोग अस्पताल ले गए। बाराबंकी से भी फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गई हैं। हादसा जिला मुख्यालय से 20 किमी दूर गुडंबा थाना क्षेत्र के बेहटा में हुआ है।

राज्यपाल श्री पटेल ने किया राजभवन में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने राजभवन में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। राज्यपाल श्री पटेल ने रविवार को राजभवन के गेट क्रमांक एक और मंदिर पुनर्निर्माण के प्रगतिरत कार्यों का मुआयना किया। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव भी मौजूद थे।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल प्रातः राजभवन परिसर में निर्माणाधीन मंदिर पहुंचे। निर्माण एंजेंसी के अधिकारियों के साथ चर्चा की और निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कार्य समय-सीमा में पूरा करने और गुणवत्ता पर विशेष बल देने के लिए कहा। राज्यपाल को बताया गया कि मंदिर सुदृढ़ीकरण कार्य के तहत कुल 27 सौ वर्गफुट का मंदिर हॉल, 1120 वर्गफुट की भोजन शाला और भंडारा कक्ष एवं 560 वर्गफुट में रसोई का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर पुनर्निर्माण कार्यों की कुल लागत 84 लाख 13 हजार रुपये है। परियोजना के तहत 76 लाख 96 हजार रुपए के सिविल कार्य और 7 लाख 16 हजार रुपये के इलेक्ट्रिक कार्य किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने इससे पहले राजभवन के गेट क्रमांक एक के निर्माण की स्थिति को देखा। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

राज्यपाल पटेल ने सुनी कार्यक्रम मन की बात

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात को राजभवन में सुना। कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था राजभवन के सांदीपनि ऑडिटोरियम में की गई थी। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण ऑडिटोरियम की विशाल स्क्रीन पर किया गया।

रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थें। कार्यक्रम में अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, जनजातीय प्रकोष्ठ की सचिव श्रीमती जमुना भिड़े सहित राजभवन के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

उमा भारती ने साफ-साफ जता दिया अपना इरादा

मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं

भोपाल (नप्र)। राजनीति एक मंच है और योगदान मेरी क्षमता है, कोई भी व्यक्ति योगदान करने की अंतिम आयु तय नहीं कर सकता ... यह कहना है वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का। उन्होंने शनिवार को कहा कि कोई भी राजनीतिक दल सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति योगदान करने की क्षमता की अंतिम आयु निर्धारित नहीं कर सकता है। समाचार एजेंसी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में, उमा भारती ने कहा कि वह अगला चुनाव लड़ेंगी जब उन्हें लगेगा कि वह तैयार हैं क्योंकि उनके पास लोगों की शक्ति है।

राजनीति में उम्र पर सवाल

उमा भारती से उनकी पिछली टिप्पणी के बारे में पूछा गया था कि राजनीति में सेवानिवृत्ति की कोई उम्र नहीं होती है। भारती ने कहा, कोई भी संगठन, राजनीतिक दल, संस्था सेवानिवृत्ति की आयु तय कर सकती है, लेकिन योगदान की नहीं। योगदान की कोई उम्र नहीं होती। जब उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब है कि वह अनिश्चित काल तक राजनीति में बने रहने का इरादा रखती हैं, तो भारती ने स्पष्ट किया, राजनीति एक मंच है और योगदान मेरी क्षमता है, भगवान ने मुझे यह दिया है और यह मेरे अंतिम समय तक मेरे साथ रहेगा।

चुनाव लड़ने के लिए कहा 'हां'

यह पूछे जाने पर कि क्या वह अगला चुनाव लड़ेंगी, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, 'हां... मैं चुनाव तब लडूंगी जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूं... मेरे पास लोगों की शक्ति है...' उन्होंने आगे कहा, '65 साल की उम्र में, पीएम मोदी ने अपना लोकसभा चुनाव लड़ा। मैं अगले साल 65 साल की हो जाऊंगी। अगर मैं अभी कोशिश करती हूं, तो मुझे कुछ बाधाएं आएंगी...'।

प्रतिबद्धताओं के प्रति ईमानदार

उन्होंने लोगों और जिम्मेदारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समझाते हुए कहा, मेरी एक कमजोरी है कि मैं अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति बहुत ईमानदारी से समर्पित हूं। अगर मुझे संसदीय सीट के लिए चुनाव लड़ना है तो मुझे अपना सारा समय और ईमानदारी वहां के लोगों को समर्पित करनी पड़ेगी। अगर किसी को कोई कठिनाई होती है, तो मुझे उसके बारे में दोषी महसूस होगा। मैं एक उद्देश्य-उन्मुख व्यक्ति हूं और चुनाव लड़ने का मेरा निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरा उद्देश्य बाधित होगा या नहीं।

उतार-चढ़ाव भरा रहा राजनीतिक करियर

उमा भारती का राजनीतिक सफर महत्वपूर्ण उतार-चढ़ावों से भरा रहा है। 2003 में मध्य प्रदेश में भाजपा को जीत दिलाकर दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन को समाप्त करने के बाद, उन्हें बाद में 2012 में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया। एक प्रमुख हिंदुत्व नेता होने के बावजूद, उन्हें मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए एक संभावित गुट के रूप में देखा गया। हालांकि, भारती की दृढ़ता का फल तब मिला जब उन्होंने 2014 में झांसी से संसदीय चुनाव जीता और नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनीं। मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 2017 में समाप्त हो गया, जिससे उन्हें यह घोषणा करनी पड़ी कि वह 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी।

ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोलीं

इसके अलावा, जब पूछा गया कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य प्राप्त हो गया है, तो उमा भारती ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को वापस लेना एक राष्ट्रीय उद्देश्य बना हुआ है। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद, यह माना जाएगा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' का उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त हो गया है।

स्वदेशी ही समृद्धि का आधार है : राज्यमंत्री श्रीमती गौर

स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के समापन कार्यक्रम में शामिल हुई

भोपाल (नप्र)। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा कि स्वदेशी से स्वावलंबन और स्वावलंबन से सशक्त भारत बनता है। यह बात रविवार को भोपाल स्थित राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में आयोजित दो दिवसीय स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान के अखिल भारतीय महिला प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में कहीं।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को गढ़ने में महिलाओं की सहभागिता देश के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक महिलाओं ने हमेशा निर्णायक भूमिका निभाई है।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने देश के विभिन्न राज्यों से आयी 124 प्रतिभागी महिलाओं को संबोधित करते हुए स्वदेशी विचारधारा, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि स्वदेशी मूल्यों पर आधारित यह अभियान न केवल महिला शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में हमारी सक्रिय भूमिका को भी सुदृढ़ करता है। हर घर में स्वदेशी का आह्वान आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठक स्वदेशी जागरण मंच श्री कश्मीरी लाल जी, अखिल भारतीय महिला प्रमुख स्वदेशी जागरण मंच श्रीमती अर्चना मीना, निदेशक एन. आई. टी. टी. आर, भोपाल प्रो. चंद्र चारु त्रिपाठी, डॉ. प्रतिभा चतुर्वेदी, डॉ. रश्मि विजय सहित कई पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

भाजपा ने निकाली राहुल के पुतले की अर्थी

सीएम बोले- परेशानी है तो नाना-नानी के पास जाएं; बिहार में पीएम को कहे गए थे अपशब्द

भोपाल (नप्र)। बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की सभा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने के विरोध में रविवार को भोपाल में भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले की अर्थी निकाली।

प्रदर्शन के लिए भाजपा महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भोपाल के रेड क्रॉस चौराहे पर इकट्ठी हुईं और नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ने लगीं। हालांकि, पुलिस ने उन्हें सिद्धांता हॉस्पिटल के सामने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया।

उधर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए गलत बयान दे रहे हैं। इतनी ही परेशानी है तो उन्हें अपने नाना-नानी के पास चले जाना चाहिए। इस जगत में रहने का उन्हें कोई हक नहीं है।

दोनों तरफ दौड़ लगाते गार्ड और बीच में शिवराज

एनर्जी से लबरेज 'मामा' ने चलाई साइकिल, दे दिया ये बड़ा संदेश

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वे लोगों के बीच हमेशा एक नई ऊर्जा के साथ दिखाई देते हैं। जब शिवराज अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा पहुंचे तो उन्होंने 2 किमी तक साइकिल चलाई। शिवराज की एनर्जी देख हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने भारत को स्वस्थ बनाने का संदेश दिया।

दरअसल, शिवराज सिंह चौहान कल अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा दौरे पर थे। वे पूरे अलग-अलग कार्यक्रमों में पहुंचे। और पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह से लबरेज नजर आए। विदिशा में खेल महोत्सव के अंतर्गत आयोजित खेल दिवस कार्यक्रम के मंच पर जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो युवाओं का जोश देखने लायक था।

दो किमी तक चलाई साइकिल

युवाओं से बातचीत के बाद शिवराज सिंह खुद भी मैदान में उतर आए। उन्होंने युवाओं व स्कूली बच्चों के साथ एसआईटी कॉलेज से लेकर आरटीओ दफ्तर तक लगभग दो किलोमीटर तक साइकिल चलाई। साइकिल पर एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था कि मन में रखो एक ही सपना, स्वस्थ बनाना है भारत अपना। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में शिवराज साइकिल चला रहे हैं और उनके दोनों तरफ सुरक्षा गार्ड दौड़ लगा रहे हैं।

मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर किया था स्वदेशी अपनाने का पोस्ट

इससे पहले केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा था कि स्वदेशी ही भारत की असली शक्ति है। अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें स्वदेशी को अपनाना होगा। स्वदेशी सिर्फ वस्त्र या वस्तु नहीं, यह आत्मनिर्भरता का मंत्र है। यह हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, हमारे कारीगरों के हुनर की पहचान है और हमारे उद्योग व युवाओं की ताकत है।

श्री हिंदू उत्सव समिति का चुनाव, पांच उम्मीदवारों की दावेदारी

11 हजार से अधिक सदस्य करेंगे फैसला

भोपाल (नप्र)। राजधानी की सबसे प्रभावशाली संस्थाओं में से एक श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए रविवार को मतदान हुआ। गुफा मंदिर, लालघाटी स्थित मानस भवन में सुबह 9 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी जो शाम 5 बजे तक चली। इस चुनाव में समिति के 11 हजार से अधिक आजीवन सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।अध्यक्ष पद की इस प्रतिष्ठित जंग में पांच दावेदार मैदान में हैं। इनमें चंद्रशेखर तिवारी, दीपेश श्रीवास्तव, कैलाश बेगवानी, हेमंत कुशवाह और नारायण कुशवाह शामिल हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. पीसी कोठारी ने बताया कि मतदान के लिए समिति द्वारा जारी आजीवन सदस्यता कार्ड, आधार कार्ड अथवा भारत निर्वाचन आयोग का फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य होगा। इसके अलावा मतदाता का नाम समिति की सदस्यता सूची में होना जरूरी है।

एम्बुलेंस नहीं आई, स्वास्थ्य केंद्र बंद मिला...सड़क पर डिलीवरी

विदिशा में परिजन बोले- मां, बच्ची को लोडिंग से अस्पताल पहुंचाना पड़ा; 4 कर्मचारियों को नोटिस

विदिशा (नप्र)। विदिशा जिले के शमशाबाद में शनिवार को एक महिला ने सड़क पर बच्ची को जन्म दिया। परिजन का आरोप है कि कई बार फोन करने पर एंबुलेंस नहीं आई। मजबूरी में वे महिला को बाइक पर बैठाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचे। यहां ताला लगा था।

परिजन महिला को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए निकले लेकिन रास्ते में ही प्रसव हो गया। ये देखकर स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। मां और नवजात को लोडिंग वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया। शमशाबाद में गेंदा वर्री गांव की रहने वाली ममता बाई को रात करीब 10 बजे प्रसव पीड़ा हुई। पति शैतान सिंह और ससुर घीसा लाल उसे बाइक पर लेकर बरखेड़ा जागीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां अस्पताल बंद था। इसके बाद वे शमशाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर निकले। रास्ते में गिरधर मार्केट के पास महिला को तेज दर्द हुआ। कराहते हुए उसने सड़क पर ही बच्ची को जन्म दिया। परिजन की गुहार पर स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। गद्दा-चादर देकर मां-बेटी को लोडिंग वाहन से शमशाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा।

परिजन बोले- एम्बुलेंस को कॉल किया था

ममता के पति शैतान सिंह ने कहा- हमने कई बार एम्बुलेंस को कॉल किए। हर बार कहा गया कि एम्बुलेंस आ रही है लेकिन वे नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा- यदि बरखेड़ा जागीर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुला होता, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती।शमशाबाद स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ के मुताबिक, मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। उनकी उचित देखभाल की जा रही है।

बीएमओ बोलीं- जांच के बाद कार्रवाई करेंगे

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर नीतू राय ने कहा- मामले में स्टाफ नर्स प्रीति गुनकर, लक्ष्मी चौकसे, फार्मासिस्ट मुकेश और डॉ. विनय ठाकुर को शो-कॉज नोटिस दिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।राय ने कहा- ममता के परिजन ने बरखेड़ा जागीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाने की बात कही है। वहां की स्टाफ नर्स लक्ष्मी चौकसे ने बताया कि वह रात 10:30 बजे तक केंद्र पर मौजूद थी, उस दौरान कोई भी नहीं आया।रात के समय पीएससी के मुख्य गेट पर ताला रहता है, लेकिन साइड का छोटा गेट खुला रहता है। आशा कार्यकर्ता ने जब एम्बुलेंस बुलाने की बात कही तो ममता के परिजन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस अक्सर देर से आती है, इसलिए वे बाइक से ही शमशाबाद जा रहे थे।

स्वास्थ्य केंद्र में चार लोगों का स्टाफ

बीएमओ नीतू राय ने बताया- बरखेड़ा जागीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चार लोगों का स्टाफ तैनात है, जिनकी 24 घंटे की ड्यूटी निर्धारित है। सुबह से दोपहर 2 बजे तक और शाम को 1 घंटे के लिए ओपीडी खुलती है। बाकी समय स्टाफ अपने घर पर मौजूद रहता है। किसी भी इमरजेंसी केस की स्थिति में स्टाफ तुरंत पीएससी पहुंच जाता है।स्टाफ नर्स प्रीति गुनकर के पिता को हार्ट अटैक आने के कारण वह पिछले तीन दिन से अवकाश पर है। ऐसे में डिलीवरी केस एएनएम प्रेमा विशिष्ट की मदद से कराए जा रहा हैं।पीएससी पर करीब 50 हजार जनसंख्या का भार है। इस महीने बरखेड़ा जागीर पीएससी में अब तक लगभग 7 डिलीवरी हो चुकी हैं।

मंत्री श्री सारंग के नेतृत्व में निकली 5 किमी लंबी फिट इंडिया साइकिल रैली

वॉटर स्पोर्ट्स शो में खिलाड़ियों ने बड़े तालाब में दिखाये करतब

राष्ट्रीय खेल दिवस पर तीन दिवसीय खेल महोत्सव का हुआ समापन

भोपाल (नप्र)। राष्ट्रीय खेल दिवस के अंतर्गत आयोजित तीन दिवसीय खेल महोत्सव का समापन रविवार को राजधानी भोपाल में फिट इंडिया साइकिल रैली और वॉटर स्पोर्ट्स शो के साथ हुआ। साइकिल रैली का नेतृत्व सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा भारतीय खेल प्रधिकरण भोपाल शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित साइकिल रैली का शुभारंभ वीआईपी रोड स्थित राजाभोज प्रतिमा से हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में साइकिलिस्टों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली वीआईपी रोड होते हुए लेक व्यू स्थित वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी तक पहुँची। पूरे मार्ग में फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और अनुशासन का संदेश जन-जन तक पहुँचाया गया।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे देश को फिट इंडिया मूवमेंट का आहवान किया था और उनका मंत्र है 'फिट इंडिया से ही हिट इंडिया होगा'। 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम ने उसी संदेश को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय इस खेल महोत्सव के दौरान पूरा प्रदेश खेलमय हो गया और राजधानी भोपाल ने इस आयोजन के माध्यम से पूरे देश को स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया है। मंत्री श्री सारंग ने साइकिल राइडर एसोसिएशन को बधाई देते हुए कहा कि साइकिल चलाना केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि यह हमारी जीवनशैली में अनुशासन और संतुलन लाने वाला साधन है। प्रदेश में हम साइकलिंग को और बढ़ावा देने के लिये सार्थक प्रयास करेंगे।

साइकिल रैली के समापन पर वॉटर स्पोर्ट्स अकादमी में भव्य जल क्रीड़ा गतिविधियों का आयोजन हुआ। यहाँ खिलाड़ियों ने बड़े तालाब में अपने खेल कौशल का रोमांचक प्रदर्शन किया। कायकिंग, कैनोइंग, स्लैलम और सेलिंग जैसी प्रतियोगिताओं ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने राजधानी में खेल महोत्सव के समापन को यादगार बना दिया और यह आयोजन लंबे समय तक खेल प्रेमियों की स्मृतियों में अंकित रहेगा।

इस अवसर पर भोपाल सांसद श्री आलोक शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संचालक श्री राकेश गुप्ता, उप निदेशक श्री बी.एस. यादव, भारतीय खेल प्राधिकरण के मध्य क्षेत्रीय केन्द्र भोपाल के क्षेत्रीय निदेशक श्री अभिषेक सिंह चौहान सहित विभागीय अधिकारी, खेल संगठन और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

संपादकीय

ट्रंप की भारत से नाराजी की वजह!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से इतने खफा क्यों हैं, इसके पीछे के कारण का जो खुलासा वहां के अखबार 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने किया है, वह चौंकाने की बजाए हास्यास्पद ज्यादा है। अखबार के मुताबिक ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान व भारत के बीच संघर्ष को रुकवाने का श्रेय लेना चाहते थे कि पाकिस्तान की तरह भारत भी उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नामांकित करे। भारत ट्रंप के इरादों को भांप गया था। उसने न केवल संघर्ष विराम कराने के ट्रंप के दावों को खारिज किया बल्कि नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करने की अपेक्षा को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। शायद इसी वजह से ट्रंप नाराज हैं और मनमानी किए जा रहे हैं। अखबार के मुताबिक ट्रंप का भारत के प्रति रवैया 17 जून के एक फोन के बाद कठोर होता चला गया। 17 जून को जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पूरी तरह रुक चुका था तब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री को फोन किया। इस फोन में उन्होंने दावा किया कि वह दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष खत्म कराने के लिए गौरवान्वित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने वाला है। एनवाईटी के मुताबिक, यह पीएम मोदी को सीधा इशारा था कि वह भी ऐसा ही करें। अखबार ने इस फोन कॉल की जानकारी रखने वालों के हवाले से दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रही। यह भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी बातचीत के बाद हुआ है। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी को नजरअंदाज करने की कोशिश की। हालांकि, भारतीय पीएम की तरफ से जताई गई असहमति और नोबेल शांति पुरस्कार के मामले में कुछ न कहना, दोनों नेताओं के रिश्तों में खटास पैदा कर गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस फोन कॉल पर उसकी रिपोर्ट अमेरिका से लेकर भारत तक दर्जन भर अधिकारियों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। इनमें से अधिकतर लोगों ने अपने नामों का खुलासा न करने की शर्त पर अखबार से बात की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे अहम साझेदार के साथ रिश्ते खराब करने की कोशिश में जुटे हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं, जिनकी वजह से ट्रंप और मोदी के रिश्ते बिगड़े। ये हैं अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के निर्वासन व एच एन बी वीजा की समीक्षा का मामला, ट्रंप द्वारा वाशिंगटन आने के न्यौते से मोदी का इंकार, अतिरिक्त टैरिफ लगाने के मुद्दे पर भारत द्वारा समझौते की पहल न करना, व्यापार समझौते के लिए मोदी द्वारा ट्रंप का फोन न उठाना शामिल है। इस बीच भारत अपनी विदेश नीति की फिर से समीक्षा करके रूस,चीन, भारत गठजोड़ को मजबूत करने में लग गया है। अमेरिका को इससे भी मिर्ची लगी है। संदेश साफ है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में न तौले और ट्रंप फोकट का श्रेय न लें। जहां तक नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप के नामांकन का सवाल है तो उन्होंने ऐसा किया ही क्या है कि भारत उन्हें विश्व के इस सबसे बड़े पुरस्कार के लिए नामांकित करे। वो केवल धमकियां देने का काम कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार इस योग्यता के लिए तो नहीं मिलता। इस बीच यह खबर भी आई है भारत से चिढ़े ट्रंप इस साल भारत में होने वाले क्वाड सम्मेलन में भाग लेने नहीं आएंगे। अमेरिका याद रखे कि यदि भारत क्वाड में निष्क्रिय हुआ तो उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी।

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।

संविधान संशोधन एक चतुराई भरा कदम

पिछले दिनों जिस प्रकार सरकार ने ईडी सीबीआई आदि संस्थाओं का दुरुपयोग किया है उससे प्रतिपक्ष की चिंता भी निराधार नहीं कहीं जा सकती। कितना विचित्र है कि दो-दो साल तक मंत्री जेल में रहे और उसके बाद भी एजेंसी अपराध का कोई प्रमाण न दे सके और फिर स्वतः खात्मा लगा दे। होना तो यह चाहिए कि एजेंसी पहले प्रमाण जुटाए तब गिरफ्तार करे न कि प्रमाण मिलने के पहले ही गिरफ्तार करने के अवैधानिक हथियार की शक्ति का प्रयोग करे। ऐसी घटनाएं कोई एक दो नहीं है बल्कि बीसियों हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं कि जहां किसी विरोधी पक्ष के नेता के सत्ताधारी दल में शामिल होने के बाद उसके खिलाफ एजेंसी स्वतः अपना केस वापस ले ले और खात्मा लगा दें।

भारत सरकार ने अचानक 20 अगस्त को संसद में एक बिल प्रस्तावित किया जिसे 130 वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 बताया गया। इस संशोधन प्रस्ताव के माध्यम से यह प्रस्तावित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो किसी संवैधानिक पद पर है गिरफ्तार किया जाता है और 30 दिन में वह जमानत या अन्य कारण से जेल के बाहर नहीं आता तो उसे अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। संशोधन विधेयक पेश करते हुए गृहमंत्री जी ने कहा कि यह विधेयक सार्वजनिक जीवन में शुचिता लायेगा और इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी कोई छूट नहीं है। यानी यह निष्पक्ष विधेयक है। इस विधेयक का प्रतिपक्षी दलों ने विरोध किया। आमचलन के अनुसार जोरदार हंगामा हुआ और विधायक को विचारार्थ संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 29 लोग होंगे और संसदीय परंपरा के अनुसार स्वाभाविक है कि इसमें सत्ता पक्ष के लोग उसकी संख्या की तुलना के अनुसार ज्यादा होंगे। इस समिति को संसद के अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

प्रतिपक्षी दलों का कहना है कि यह संशोधन संविधान के अंतर्गत विरोधी दलों की सरकारों को अस्थिर करने और उन्हें भयभीत करने के उद्देश्य से लाया गया है। विरोधीदलों का संशय भी निराधार नहीं है और सत्ता पक्ष के लिए पिछले दिनों की कुछ घटनाएं मजबूत तर्क के रूप में है। जिन्हें उद्धृत करते हुए श्री अमित शाह गृहमंत्री ने संसद में कहा कि कुछ लोग जेल से सरकार चलाते हैं। मुख्यमंत्री या मंत्री के पद पर रहते हुए जेल जाने पर भी इस्तीफा नहीं देते और नैतिक मानदंडों का पालन नहीं करते। उन्होंने यह भी बताया कि जब मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो मैंने इस्तीफा दे दिया था और मुकदमे के खात्मे के बाद ही पुनरू सरकार में आए। एक अर्थ में उनका यह कहना सही है कि वर्ष 2020 तक यह परंपरा रही है कि अगर कोई मंत्री गिरफ्तार होता था तो वह इस्तीफा देता था। क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी अपराध के संशय में जेल में जाता है तो उसका पद पर बने रहना संवैधानिक परंपरा और नैतिकता के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। इस संशोधन विधेयक के पेश होने के बाद सारे देश में और मीडिया में भी बहस चल रही है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री ए. के. पटनायक ने भी इस विधेयक को असंवैधानिक बताया है और उनका मत है कि सर्वोच्च न्यायालय इसे खारिज करेगा ऐसा उनका मत है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र के हाथ में सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां हैं जो सुनिश्चित कर सकती है कि किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को कितने दिन जेल में रखना है। इससे केंद्र सरकार मुख्यमंत्री या मंत्रियों का पद छीन सकेगी। यदि सरकार कमजोर हुई तो मुख्यमंत्री के हटते ही डगमगा जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अतीत में देखा गया है कि कई मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन से अधिक जेल में रहे लेकिन उनके खिलाफ आज तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि अगर कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बरी होते हैं तो झूठा फसाने वाले उन अधिकारियों व एजेंसियों के मुखिया और सरकार के पीएम सीएम भी जेल भेजे जाएं। भाजपा की ओर से अधिकृत या अनाधिकृत रूप से राज्यसभा के पूर्व महासचिव श्री बी, के, अग्निहोत्री ने कहा है कि राजनीतिक शुचिता की दृष्टि से यह अच्छा कदम है। अगर कोई सिविल सर्वेंट किसी भी कारण से 48 घंटे से अधिक जेल में रहता है तो सिविल सेवा के नियमों के तहत उसे निलंबित मान लिया जाता है। जमानत के बाद भी उसे बहाली के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। अगर कोई सीएम या मंत्री जेल में रहने के चलते कुर्सी गवाता है तो पार्टी किसी और नेता को सीएम या मंत्री बना सकती है और पार्टी सत्ता में रहेगी। इसलिए इस उपाय का स्वागत किया जाना चाहिए। श्री अग्निहोत्री जी के तर्क निराधार लगते हैं। अधिकारी का निलंबन होता है और अगर उसे बहाली के लिए मशक्कत करना पड़ती है तो यह नियम कायदों की खामी है और सक्षम अधिकारियों का कदाचरण है। इस बहस को अगर बारीकी से देखा जाए तो इसका मूल कारण तो सत्ता के प्रति और सरकारी एजेंसियों के प्रति अविश्वास है जो की स्वाभाविक ही है।

पिछले दिनों जिस प्रकार सरकार ने ईडी सीबीआई आदि संस्थाओं का दुरुपयोग किया है उससे प्रतिपक्ष की चिंता भी निराधार नहीं कहीं जा सकती। कितना विचित्र है कि दो-दो साल तक मंत्री जेल में रहे और उसके बाद भी एजेंसी अपराध का कोई प्रमाण न दे सके और फिर स्वतः खात्मा लगा दे। होना तो यह चाहिए कि एजेंसी पहले प्रमाण जुटाए तब गिरफ्तार करे न कि प्रमाण मिलने के पहले ही गिरफ्तार करने के अवैधानिक हथियार की शक्ति का प्रयोग करे। ऐसी घटनाएं कोई एक दो नहीं है बल्कि बीसियों हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं कि जहां किसी विरोधी पक्ष के नेता के सत्ताधारी दल में शामिल होने के बाद उसके खिलाफ एजेंसी स्वत अपना केस वापस ले ले और खात्मा लगा दें। महाराष्ट्र एनसीपी के नेता और शरद पवार के भतीजे श्री अजीत पवार के खिलाफ 1000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा ने और सीबीआई ने भी लगाए थे परंतु जब वे एनसीपी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए तो सीबीआई ने खात्मा लगा दिया और श्री पवार को मंत्री बना दिया। जब वे पुनरू भाजपा छोड़कर एनसीपी में चले गए तो केंद्र के इशारे पर सीबीआई ने फिर उनके खिलाफ प्रकरण शुरू करने की अर्जी लगा दी। और फिर जब वे पुनः भाजपा के समर्थन में चले गए तो न केवल उपमुख्यमंत्री हैं बल्कि इस एजेंसी ने फिर मामला वापस कर लिया। लगभग ऐसी ही घटना प्रफुल्ल पटेल की भी है जो एनसीपी के पक्ष से केंद्र सरकार में मंत्री थे। केंद्र सरकार एजेंसियों का इस प्रकार बेशर्म प्रयोग राजनीतिक भयादोहन और दल बदल करवाने के लिए करती रही है। अतरू केंद्र सरकार की नियत और सत्ता की दास एजेंसियों की कार्यवाही कैसे विश्वसनीय मानी जा सकती है? जो लोग निष्पक्षता या शुचिता का तर्क दे रहे हैं वह तर्क पढ़ने और सुनने में अच्छा लगता है,परंतु देश में नौकरशाही का जो चरित्र है उसमें क्या उनसे यह उम्मीद की जा सकती है कि वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या सत्ता पक्ष के मंत्री के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेंगे? कुल मिलाकर अभी तक के राजनीतिक अनुभव और आम तौर पर सभी सरकारों के चरित्र को देखते हुए इन प्रावधानों की शब्दावली और शुचिता के दावे पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? फिर दूसरा एक वैधानिक, नैतिक और तार्किक पक्ष भी है, कि क्या किसी व्यक्ति को किसी एजेंसी के द्वारा आरोपी बना दिए जाने मात्र से उसे दोषी मान लिया जाए। दोषी सिद्ध करने का अधिकार न्यायपालिका का है। अभी तक यह कानून है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा हो जाती है तो वह पद पर रहने के अयोग्य हो जाता है परंतु इस संशोधन से तो केवल आरोप लगने पर ही व्यक्ति को अपराधी मान लिया जाएगा और पद से हटने के दंड का भागी माना जाएगा। यह संशोधन न्याय के मूल सिद्धांत के ही खिलाफ है। श्री अमित शाह का राजनीतिक जीवन आपातकाल के बाद का है परंतु उन्हें अपनी मातृ संस्था के प्रमुखों से जानना चाहिए कि जिस आपातकाल का वे विरोध करते हैं और कांग्रेस के द्वारा लगाए गए जिस आपातकाल ने उनकेऔर उनकी पार्टी के लिए सत्ता के दरवाजे खोले हैं उसमें क्या हुआ था? जब सरकार का आदेश हुआ कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, मोरारजी देसाई को गिरफ्तार करना है और आरोप बनाने और लगाने का काम सरकारी एजेंसी को करना है तो पुलिस ने जयप्रकाश नारायण को राजद्रोह का अपराधी और पुलिस तथा सेना में विद्रोह फैलाने का उत्तरदायी बता दिया था। मोरारजी देसाई को तो यह आरोप पत्र दिया गया था कि वह सरकार के टेलीफोन के खंभे पर चढ़कर तार काट रहे थे इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस पुलिसकर्मी का कोई दोष नहीं है क्योंकि उसे तो झूठा आरोप लिखना है। केंद्रीय जांच एजेंसियां और पुलिस लगभग सत्ता पक्ष के सही या गलत आदेशों का पालन करने वाली बन जाती है। मेरी राय में शुचिता और नैतिकता के लिए कानून बनाया जाए तथा कानून निम्न प्रकार का हो सकता है।

1. न्यायपालिका को 29 दिन में निर्णय देने की वाध्यता हो और उसके बाद आगामी 30 दिनों में अपीलीय न्यायपालिकाएं आवश्यक निर्णय करें। अगर न्यायपालिकाएं अंतिम अपीलीय स्तर पर किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को दोषी सिद्ध करें तब उसे इस्तीफा देने या हटाए जाने का नियम बने।
2. यह भी कानून बने की जांच एजेंसियां गिरफ्तार करने के 7 दिन के अंदर चालान पेश करें। अगर नहीं कर पाती हैं या न्यायपालिका को संतुष्ट करने लायक प्रमाण पेश नहीं कर पाती हैं तो प्रकरण को निरस्त किया जाए।
3. जो जांच एजेंसियां आरोप लगा रहीं हैं और अगर वे निर्णय के पूर्व यह स्वीकार करतीं हैं कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो गिरफ्तार करने वाली एजेंसी के मुख्य अधिकारी को दंडित किया जाए।
4. अगर न्यायपालिका अपने फैसले में यह दर्ज करती है की जांच एजेंसी ने जानबूझकर लापरवाही की है या किसी के दबाव में आकर झूठी कार्रवाई की है, तो उस एजेंसी के जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज हो जो गैर जमानती हो।
5. सुचिता के लिए यह भी संवैधानिक प्रावधान बने कि अगर सत्ता पक्ष अपनी सरकार के विरोधी व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति पर उनकी जांच एजेंसी के द्वारा आरोप लगाने के बाद , उसे अपने पक्ष में शामिल करते हैं तो उसे राजनीतिक अपराध माना जायेगा तथा उस सत्ताधारी पार्टी को जिम्मेदार मानकर उसकी मान्यता समाप्त की जायेगी।

भारत सरकार के 130 वें संविधान संशोधन से जितने भयभीत विरोधी दल हैं जो स्वाभाविक भी है ,उससे ज्यादा भयभीत सत्ता पक्ष के सत्ता संचालक गुट से भिन्न सत्ता के लोग हैं। क्योंकि इस संशोधन के हथियार का इस्तेमाल जितना प्रतिपक्ष के खिलाफहो सकता है उतना ही सत्ता पक्ष के अंतर विरोधियों के खिलाफ भी हो सकता है। प्रतिपक्ष तो कम से कम आलोचना भी कर सकेगा पर सत्ता पक्ष का अंतरविरोधी तो यह भी नहीं कर सकेगा। यह संशोधन एक भयावह तानाशाही और लोकतंत्र के खात्मे का कारण बन सकता है।

बहरहाल यह संशोधन होगा या नहीं होगा यह तो अभी भविष्य के गर्भ में है तथा मीडिया और जनता में चर्चा में है परंतु एक लाभ तो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री को और उनकी पार्टी को हो ही गया है कि जो मीडिया वोट चोरी के आरोपी की चर्चाओं से भरा हुआ था अब वह इस संशोधन की आड़ में पीछे छूट गया। यह संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव एक चतुराई भरा राजनीतिक षड्यंत्र है,यह शायद प्रतिपक्ष भी नहीं समझ पाया।

मुद्दा

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सड़क हादसे : बेसुध प्रशासन, लाचार सरकार

देश में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर 2023 की नई रिपोर्ट आई है, लेकिन हाल वही पुराना है। बीते वर्ष की तुलना में 4.2 प्रतिशत हादसे बढ़ गए, इनमें जान गवांने वालों की संख्या भी बढ़ गई। शासन और प्रशासन ने बड़े हादसों का ठीकरा वाहनों की तेज रफ्तार पर फोड़कर अपनी चिंता पूरी कर ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी सड़क हादसों का दोशी अकर्मण्य आधिकारियों को जता देते हैं, लेकिन जब यह निकम्मे हैं, तो इन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती। अतएव रिपोर्ट का निश्कर्ष है कि प्रशासन बेसुध है और सरकार नौकरशाही के आगे लाचार है।

देशभर में इस साल जनवरी से जून के बीच केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई दुर्घटनाओं में 26,770 लोगों ने प्राण गंवा दिए हैं। नीतिन गडकरी ने संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा में लिखित जानकारी सांसद संबित पात्रा के प्रश्न के उत्तर में दी थी। गडकरी ने बताया था कि सरकार 2022 से प्रत्येक वर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले आंकड़ों के आधार पर भारत में 'सड़क दुर्घटनाएं' शीर्षक से रपट प्रकाशित करती है। देशभर में हुई सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के प्रबंधन और विश्लेषण के लिए 'इलेक्ट्रोनिक डिटेल' एक्सिडेंट रिपोर्ट (ई-डार) पोर्टल विकसित किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 53,372 लोगों ने और 2024 में 52,609 लोगों के प्राण चले गए थे और 2025 के बीते छह माह में 26,770 लोगों की मौतें हुई हैं। देश में सड़कों पर एक्सप्रेस हाइवे, चौड़ीकरण और ग्रामों में सड़कों के विस्तार के चलते जिस अनुपात में रफ्तार की सुविधा बढ़ी है, उसी अनुपात में दुर्घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पूरे देश में एक्सप्रेस-वे पर निरंतर दुर्घनाएं घट रही हैं। यह चिंता की बात है कि आखिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं? केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में जानकारी दी थी कि देशभर में हई कुल सड़क दुर्घटनाओं में 32.9 प्रतिशत एक्सप्रेस-वे पर घटी हैं। इनकी वजह तेज गति रही है। साल है कि जब तेज रफ्तार से हादसे हो रहे हैं, तो इन्हें रोकने के उपाय क्या किए जा रहे हैं। पश्चिमी देशों में तो गति राडार लगाए गए हैं। व्यावसायिक वाहनों में भी स्पीड गवर्नर लगाने की योजना है, लेकिन वह ठंडे बस्ते में पड़ी है। यह योजना इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसे वाहन की ईंधन प्रदाय प्रणाली से जोड़ा जाता है, जो गति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त तेल इंजन में जाने ही नहीं देती है। दुर्घटनाओं के बढ़ने का एक बड़ा कारण देश को कार और दो पहिया वाहनों से पाट देना भी है। शराब पीकर वाहन चलाना भी दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। अब तक यह आम धारणा बनी हुई है कि सड़क हादसे राजमार्गों पर अधिक होते हैं। किंतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक नई तस्वीर पेश की है। इससे पता चला है कि राजमार्गों से कहीं अधिक हादसे भीतरी सड़कों पर भी होने लगे हैं। यह वाकई हकीकत है। ग्रामीण इलाकों में जबसे ट्रैक्टर, बाइक और कार-जीपों की संख्या बढ़ी है, तब से इन छोटे समझे जाने वाले मार्गों पर दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बीते दो दशकों के भीतर गांव-गांव सड़कें पहुंची हैं और उसी तादाद में वाहन भी बढ़े हैं। विडंबना यह भी रही कि इसी दौरान गांव-गांव शराब की वैध-अवैध बिक्री भी शुरू हो गई, जो दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण बन रही है। सड़क हादसों में भारत को हर साल मानव संसाधन का सर्वाधिक नुकसान उठाना पड़ता है। अंतरराष्ट्रीय सड़क संगठन (आईआरएफ) की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से ज्यादा हैं। इस जानकारी के अनुसार 12.5 लाख लोगों की दुनिया में प्रतिवर्ष सड़क हादसों में मौतें होती हैं, इनमें सर्वाधिक भारत में होती है। जो परिवार हादसे में अपने परिजन को गंवाता है, उस पर पांच लाख रुपए का औसतन अतिरिक्त बोझ पड़ता है। सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं में शराब पीकर वाहन चलाना, नाबालिग बाइकर्स का सड़कों पर बेलगाम होना भी हैं, वहीं देश में बढ़ते सड़क हादसों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों में भी तलाशे जा रहे हैं। दरअसल देश में हरेक साल करीब डेढ़ लाख लोग मारे जाते हैं और चार से पांच लाख घायल होते हैं, उनमें ज्यादातर युवा होते हैं।

दूसरी तरफ सरकार राजमार्गों पर ऐसे स्थल तलाश रही है, जहां अधिकतम दुर्घटनाएं होती हैं। इसके बाद इन स्थलों पर ऐसे सुधार किए जाएंगे, जिससे घटनाएं कम हों। राजमार्ग लंबे व तेज गति के सफर के लिए होते हैं। इसलिए अक्सर वाहनों की गति तेज रहती है। भारी मालवाहक वाहन राजमार्गों से ही गुजरते हैं। ऐसे में यदि वाहन चालकों को आसानी से षराब की उपलब्धता दिखाई दे तो उसके प्रति स्वाभाविक रूप से लालच पैदा हो जाता है। इसके सेवन के साथ ही खतरे की आशंका बढ़ जाती है। राजमार्गों पर हर पांच किलोमीटर की दूरी पर औसतन शराब की तीन दुकानें हैं। इस बाबत पूर्व प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शराब लॉबी के दबाव में अंधाधुंध परमिट बांटने की प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि, 'शराब के भयावह सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर खूब चर्चा की जाती है, लेकिन संवैधानिक निर्देश के बावजूद सरकारें शराब पर अंकुश लगाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखा पाती हैं। शराब कारोबारी भी धन के बूते ऐसी पहलों को व्यर्थ कर देते हैं और सरकारें राजस्व कमाई की दुहाई देकर शराब की बिक्री जारी रखती हैं।' पिछले डेढ़ दशक में देशभर की सड़कों पर क्षमता से अधिक वाहन आए हैं। अतएव उसी अनुपात में हादसे भी बढ़े हैं। इन हादसों में ज्यादातर मरने वाले लोगों में 40 फीसदी, 26 से 45 आयुवर्ग के होते हैं। यही वह महत्वपूर्ण समय होता है, जब इन पर परिवार के उत्तरदायित्व के निर्वहन का सबसे ज्यादा दबाव होता है। ऐसे में दुर्घटना में प्राण गवां चुके व्यक्ति के परिजनों पर सामाजिक, आर्थिक और आवासीय समस्याओं का संकट एक साथ टूट पड़ता है। इन हादसों में 19 से 25 साल के इतने युवा मारे जाते हैं, जितने लोग कैंसर, टीबी और मलेरिया से भी नहीं मरते। ये हादसे मानवजन्य विसंगतियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आबादी में पीढ़ी व आयुवर्ग के अनुसार जो अंतर होना चाहिए, उसका संतुलन भी गड़बड़ा रहा है। यदि सड़क पर गति को नियंत्रित नहीं किया गया तो सड़क हादसों में मरने वाले लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि शायद आबादी नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन की जरुरत ही नहीं रह जाएगी ?

यातायात सुचारु रूप से संचालित हो, इसके लिए जापान, अमेरिका और सिंगापुर के यातायात कानून से भी सीख लेने की बात कही जा रही है। खासतौर से यूरोपीय देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आचार संहिता लागू है, जिसका ज्यादातर देश पालन करते हैं। इस संहिता के मुताबिक यदि किसी कार की गति 35 किमी प्रति घंटा है, तो दो कारों के बीच की दूरी 74 फीट होनी चाहिए। 40 मील प्रतिघंटा की रफ्तार होने पर यह अंतर 104 फीट और 45 फीट की गति पर यह अंतर 132 फीट होना चाहिए। संहिता में चालकों के नियम भी तय किए गए हैं। यदि चालक की मुट्ठी बंद करने की ताकत पौने सोलह किलोग्राम से कम निकलती है तो माना जाना चाहिए कि यह व्यक्ति वाहन चलाने लायक नहीं है। संहिता की शर्त के मुताबिक वाहन चलाने लायक उस व्यक्ति को माना जाएगा जो 20 मीटर आगे चल रहे वाहन का नंबर आसानी से पढ़ ले। हमारे यहां तो 80 साल के षक्ति और दृष्टि से कमजोर हो चुके बुजुर्ग भी सड़कों पर वाहन चलाते खूब देखे जाते हैं। फिर वाहनों के अनुपात में हमारी सड़कों पर जगह भी नहीं है। 74 फीट दूरी बनाएं रखने की बात तो छोड़िए, देश के महानगरों में 2 से 5 फीट की दूरी वाहनों के बीच बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। जाहिर है, हम लायसेंस प्रणाली को श्रेश्ठ बनाने के लिए बात भले दुनिया के देशों का अनुकरण करने की करें, लेकिन नतीजे कारगर निकलें ऐसी उम्मीद कम ही है? लिहाजा सड़कों से वाहन कम किए बिना दुर्घटनाओं से छुटकारा मुश्किल है। दूसरी तरफ कार एवं बाइक लॉबी हमारे यहां इतनी मजबूत है कि वह कारों के उत्पादन में कमी लाने नहीं देगी, बल्कि उसकी तो कोशिश है कि कारें सड़कां पर निर्बाध चलें। इसके लिए पदयात्री, साइकिल, तांगा और साइकिल रिक्शा को ही सड़कों से हटा दिया जाए ?

जुगाड़ से मूषकराज के गणेश वाहन बनने की एक कथा

व्यंग्य

सुरेश रायकवार

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हमारे देश में तरह-तरह की जुगाड़ होती है, जैसे नौकरी की जुगाड़, नौकरी में मनचाही जगह पर पोस्टिंग की जुगाड़ अथवा क्रिकेट मैच या रेल के टिकिट की जुगाड़, मंदिर में कतार तोड़कर दर्शन की जुगाड़ आदि। ऐसे ही सरकार किसी भी पार्टी की हो, कुछ नेता सरकार में मंत्री पद की जुगाड़ कर लेते है तो कुछ बड़े-बड़े घोटालों या भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में बंद रहते भी जुगाड़ से जमानत करवा लेते है। देश में जुगाड़ के ऐसे-ऐसे खिलाड़ी पड़े हैं कि चुनाव में सबसे कम सीट आने पर भी मुख्यमंत्री पद पर बरसों-बरस कायम रहते हैं यहाँ तक कि कुछ तो अपनी अनपढ़ पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक दिलवा देते है। हम इतने जुगाडु हैं कि ट्रंप के एक देश ने हम पर टैरिफ ठोका तो हमने चालीस देशों से व्यापार करने की जुगाड़ कर ली। ओलंपिक में यदि जुगाड़ का खेल शामिल कर लिया जाए तो हमारे देश के कम से कम एक स्वर्ण पदक की तो गारंटी हो जाए।

आइए आपको जुगाड़ से मूषकराज के गणेश वाहन बनने की एक कथा सुनाते है। आजादी के कुछ ही समय बाद की बात है, एक नरक भोग रहे भारतीय चूहे ने कुछ जुगाड़ लगाई, कुछ सोचा और स्वर्ग में सेंध लगाई। लीजिये साहब, चूहा स्वर्ग में आ गया, कुछ ही दिनों में अपनी गुंडागर्दी के बल पर, स्वर्ग में छा गया। देवलोक परेशान हो रहा था, क्योंकि चूहा रोजाना कुछ नया कर रहा था, कभी किसी महल की दीवारों में छेद कर रहा था तो कभी किसी देवता के वस्त्र कुतर रहा था। स्वर्ग के नियमानुसार, उसे अब स्वर्ग से निकाला भी नहीं जा सकता था, चूहा अमृतपान कर चुका था, इसलिए अब मारा भी नहीं जा सकता था। बेचारे देवताओं ने सारे तरीके अपना लिए लेकिन, बात नहीं बन पाई। अंत में, उन्हे गणेश जी की याद आई। देवराज इन्द्र ने जब गणेश जी को चूहे की करतूत बतलाई, गजानन को सुनकर पहले तो हंसी आई। हँसते-हँसते बोले, इतनी सी बात! समस्या छोटी-सी और आपके ये हालात। अरे! जरा भारत को देखो, पूरे देश में लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, किन्तु देश के नेता केवल आपस में लड़ रहे हैं। संसद चले-ना-चले, सत्ता पाने के लिए अथवा अपने वेतन भत्ते बढ़वाने के लिए सारे नेता एकमत हो रहे है। खैर, आप निश्चिंत रहें, कल तक समस्या हल हो जाएगी। स्वर्ग को, चूहे से निजात मिल जाएगी। यह सुनकर देवता प्रसन्न हो गए, चूहे की समस्या से निश्चिंत हो गए। मगर, अब श्रीगणेश परेशान हो गए। सोचने लगे, आखिर चूहे का क्या किया जाए? चूहे को स्वर्ग से कैसे विदा किया जाए? शिवपुत्र विचार करने लगे, चूहे को धिक्कारने लगे। अंत में, एक विचार आया, दूत को भेजा और चूहे को अपने महल बुलवाया। चूहे के वहाँ पहुँचने पर, गणेश जी के दूतों ने की उसकी अगुवाई, गणेश जी ने उसे चाय पिलवाई। चाय पिलाते पिलाते ही उसे समझाया, तुम्हें सिर्फ स्वर्ग में रहना है या कुछ इज्जत भी पाना है! इज्जत की बात पर चूहा गदगद हो गया, और इसी खुशी में वह चूहा, गणपतीजी का वाहन बनने को तैयार हो गया। दूसरे दिन स्वर्ग की सभा ने यह प्रस्ताव पास कर दिया और उसी दिन से वह चूहा हमारे गणेशजी का परमानेंट वाहन हो गया। वाहन चलने लगा, समय गुजरने लगा। पिछले साठ के दशक की बात है, चूहे को स्वर्ग की एक परी पसंद आई, श्री गणेश ने उस परी से चूहे की शादी करवाई। शादी क्या हुई, इंद्रलोक में फिर आफत आ गई, तीन माह में ही स्वर्गलोक में चूहों की बाढ़ आ गई। किन्तु अबकी बार इन्द्र ने भी एक जुगाड़ भिड़ाई, चूहों को इंसान बनाकर, पहली खेप भारत भिजवाई। तब से- प्रत्येक त्रेमास में इंसान रूपी चूहों की खेप भारत आ रही है और देश में लाख प्रयास के बावजूद जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है।

मैं अपनी तथा देश की एक सौ चालीस करोड़ जनता की ओर से भगवान गणेश से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि - हे गणपति जी, स्वर्ग से दर्जनों बच्चे मृत्युलोक एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इन इंपोर्टेड बच्चों से आपके भक्तगण परेशान हो रहे हैं, सम्मेलन पर सम्मेलन हो रहे है, मगर बच्चे फिर भी बढ़ते ही जा रहे है, खाद्यान्न के भंडार समाप्त हो रहे है, किन्तु बच्चे तो प्रति घंटे आठ सौ से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ते ही जा रहे हैं। आपसे मेरी रिकवेस्ट है, कृपया हमारी समस्या पर भी गौर करना, किसी फार्मूले से हमारा भी उद्धार करना और हाँ, रिश्वत लगे तो कह देना। क्विंटलों से सिंदूर चढ़वाऊंगा, समस्या समाप्त होने पर प्रत्येक पाठक से 5001 के लड्डू और मोदक चढ़वाऊंगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

सामयिक

प्रभुनाथ शुक्ल

लेखक पत्रकार हैं।

टैरिफ नीति से नए 'ग्लोबल ट्रेड' का उदय?

अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने 'ग्लोबल ट्रेड' को लेकर एक नई बहुत छेड़ दिया है। अमेरिका की यह आर्थिक नीति दुनिया को कहां ले जाएगी यह अपने आप में बड़ा सवाल है। खुद अमेरिका के लिए यह आर्थिक और सामरिक संबंधों पर कितनी कारगर होगी यह वक्त बताएगा। ट्रंप इस आर्थिक नीति से अमेरिका को कितना समृद्ध कर पाते हैं यह देखना होगा। लेकिन ट्रंप की दादागिरी ने ग्लोबल ट्रेड नीति को बड़ा झटका दिया है। अत्यधिक टैरिफ की मार झेल रहे भारत, चीन और रूस जैसे देश नई व्यापार नीति को अंजाम देने के लिए एक मंच पर आ रहे हैं। यह दक्षिण एशिया के लिए जहाँ सुखद है। दूसरी तरफ अमेरिका के भविष्य के लिए चिंतनीय।

अमेरिकी अदालत ने ट्रंप की टैरिफ़ नीति को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद ट्रंम्प को बड़ा झटका लगा है। सरकार और अदालत के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। यह ट्रंप की विदेश नीति के खिलाफ बड़ा फैसला है। अदालत ने ट्रंम्प प्रशासन को 14 अक्टूबर तक का वक्त दिया है, सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। दुनिया के देशों के लिए यह सुखद फैसला है। क्योंकि अमेरिका में खुद ट्रंप अपनी आर्थिक नीति की आलोचना झेल रहे हैं। दूसरी तरफ अदालत के फैसले के बाद ट्रंप विरोधी और मजबूत होंगे।

अमेरिका की इस पॉलिसी से भारत जैसे देश उसके खिलाफ हो गए। जिस चीन को सबक सिखाने के लिए वह भारत के साथ खड़ा था। वहीं चीन और भारत अब अमेरिकी नीति के खिलाफ एक मंच पर आ रहे हैं। दक्षिण एशिया की दो महाशक्तियां एक मंच पर आ रही है तो ट्रेडवॉर में कुछ नया होने वाला है।जिसमें रूसी राष्टपति पुतिन की खास भूमिका है। इसका बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ सकता है। इसका असर सिर्फ आर्थिक नीतियों पर ही नहीं ग्लोबल वार, हथियार की होड़ और आर्थिक नीति पर भी पड़ेगा। ट्रंप के आगे भारत के ना झुकने की पॉलिसी ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। दुनिया में सबसे अधिक भारत पर 50 फ़ीसदी टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप की यह नीति आर्थिक रूप से भारत की कमर तोड़ने की साजिश है। ट्रंम्प भारत को झुकाना चाहते हैं और पाकिस्तान की तरह खुद का पीठलग्गू बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत के लिए यह संभव नहीं है। भारत की दुनिया में एक साख है। उसके पास विपुल आबादी है। कृषि आधारित मजबूत अर्थव्यवस्था उसका बेहद मजबूत आधार है। ऐसे हालात में भुखमरी के हालात बनने से रहे आर्थिक नुकसान भले उठाना पड़े। फिर भारत क्यों झुकेगा।

आर्थिक विश्लेषण और मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारतीय निर्यात पर काफी असर पड़ सकता है। टेक्सटाइल, कृषि उत्पादन, आर्नामेंट, चमड़ा, फुटवियर, केमिकल्स और मेडिसिन बाजार को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत से करीब 28 फीसदी वस्त्र, कालीन का निर्यात अमेरिका को होता है। भारत के संपूर्ण व्यापार निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 20 फिसदी है। भारत की जीडीपी में है दो फीसदी योगदान है। यह माना जा रहा है कि भारत को अरबों डालर का नुकसान होगा। लेकिन क्या अमेरिका के सामने झुकना भी भारत का ठीक है। समस्याएं आती हैं तो हमें विकल्प भी तलाशना होगा। जिसकी पृष्ठभूमि तैयार करने में भारत जुटा है। हालांकि ट्रंप की वजह से भारत में नौकरियां जाने का भी खतरा बना है। कई लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। श्रमप्रधान सेक्टर में सबसे ज्यादा नुकसान का प्रभाव दिख सकता है। टेक्सटाइल, आभूषण, कृषि रत्न जैसे सेक्टर में यह स्थिति दिखाई देगी। केंद्र की मोदी सरकार इससे से निपटने के लिए रणनीति भी बना रही है। फिर भी अगर अमेरिका के साथ बीच में कोई समझौता न हुआ तो भारत को आर्थिक नुकसान तो उठाना पड़ेगा। भारत को अब हर हाल में अमेरिका पर निर्भरता को कम करनी होगी। प्रधानमंत्री का जापान इसके बाद चीन दौरा इसका संकेत है। वहां चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कुछ नया गुल खिलाएगी। ग्लोबल ट्रेड पर कोई नया फैसला हो सकता है। अमेरिका की टैरिफ नीति के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बन सकती है। अगर तीनों देशों की तिकड़ी सफल हो गई तो में भविष्य में अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए टैरिफ़ नीति को अंजाम दिया। लेकिन उसकी इस पॉलिसी में साफ-सुथरी आर्थिक दृष्टि नहीं दिखती। अमेरिका की इस पॉलिसी में ग्लोबल पॉलिटिक्स की गंध आती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने उसकी भूमिका खारिज कर दी तो चिढ़ गया। भारत, रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो उसका हित टकरा गया। उसने चीन के खिलाफ जहां 30 फ़ीसदी टैरिफ लगाया वहीं भारत के खिलाफ 50 फीसदी। यह ट्रंप की पारदर्शी टैरिफ़ नीति नहीं है। ट्रंप ने भारत के खिलाफ अपनी खींझ और गुस्से का प्रदर्शन किया है। लेकिन भारत भी अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है।

भारत समेत ब्रिक्स संगठन में शामिल देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। संगठन में भारत सबसे अग्रणी। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों में टैरिफ कम करें लेकिन भारत ने इसे स्वीकार नहीं किया। जिसका नतीजा हुआ ट्रंप ने टैरिफ बम भारत पर फोड़ दिया।

हालांकि इसका दुष्प्रभाव एक पक्षीय नहीं होगा। यह अलग बात है कि भारत को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन ट्रंप की इस टैरिफ नीति ने भारत के साथ दुनिया के देशों को एक कड़ा संदेश दिया है। संदेश साफ है कि पर सबसे अधिक आत्मनिर्भरता को हर हाल में खत्म या कम करना होगा। व्यापार नीति में बदलना लाना होगा। हालांकि अमेरिका ने जो आर्थिक जंग छेड़ी है उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसका असर सिर्फ व्यापार क्षेत्र में ही नहीं पड़ेगा। सामरिक संबंधों और वैश्विक कूटनीति पर भी दिखेगा। जिसके बाद एक ग्लोबल स्तर पर तनाव की स्थिति बनेगी। दुनिया को इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी अमेरिका की होगी।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)

संदर्भ - राष्ट्रपति के सवाल-1

क्या राज्यपाल धन विधेयकों को रोक सकता है?

विधेयकों पर अनुमति के मुद्दे पर राष्ट्रपति संदर्भ की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 200 की इस व्याख्या पर चिंता व्यक्त की कि राज्यपालों को किसी विधेयक को राज्य विधानसभा को वापस भेजे बिना उसे रोकने का स्वतंत्र अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय फ़िलहाल राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए 14 प्रश्नों की सुनवाई कर रहा है। आईये जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय में इन प्रश्नों पर हुई सुनवाई में क्या कहा गया है। यह प्रश्न भी उठा कि राज्यपाल अगर अनुमति रोककर विधेयकों पर वीटों लगा सकते हैं तो इससे मनी बिल भी अवरूद्ध हो सकते हैं। राष्ट्रपति संदर्भ सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 200 की इस व्याख्या पर चिंता व्यक्त की कि राज्यपालों को किसी विधेयक को राज्य विधानसभा को वापस भेजे बिना उसे रोकने का स्वतंत्र अधिकार है। यदि इस व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि राज्यपाल धन विधेयकों को भी रोक सकते हैं, जिन्हें अन्यथा स्वीकृत करने के लिए वे बाध्य हैं। यह सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति चंदुरकर की संविधान पीठ के समक्ष हो रही है।

महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे की बहस के दौरान उन्हें संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने केन्द्र सरकार के इस तर्क का उल्लेख किया कि अनुच्छेद 200 (1) के तहत रोके रखने की शक्ति को अनुच्छेद 200 के प्रावधान के अनुसार विधेयक को विधानसभा को वापस भेजने के विकल्प के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। केन्द्र सरकार के अनुसार यदि राज्यपाल किसी विधेयक को रोक लेता है, तो इसका अर्थ है कि वह विधेयक निरस्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में राज्यपाल रोककर विधेयक पर वीटो लगा सकते हैं। केन्द्र सरकार तमिलनाडु राज्यपाल और पंजाब राज्यपाल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण से असहमत है कि यदि राज्यपाल किसी विधेयक को रोक लेता है तो उसे पुनर्विचार के लिए उसे विधानसभा को वापस भेजना आवश्यक है।

बहस के दौरान न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि ''केन्द्र का कहना है कि रोक लगाने की शक्ति अपने आप में स्वतंत्र है और राज्यपाल विधेयक को रोक सकते हैं। इसलिए जब आप स्वतंत्र रूप से रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग करते हैं तो यह थोड़ा समस्याग्रस्त होता है। क्योंकि, राज्यपाल विधेयक को शुरुआत में ही रोक लेते हैं। समस्या यह है कि इस शक्ति के साथ धन विधेयक को भी रोका जा सकता है। यह प्रावधान यहां लागू नहीं होगा। इस व्याख्या में एक बड़ी समस्या है। एक क्षण के लिए यह मान भी लें कि यह अनुमति है तो शुरूआत में भी विधेयक को रोका जा सकता है। न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि अनुच्छेद 200 के प्रावधान में कहा गया कि धन विधेयक के मामले को छोड़कर राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटा सकते हैं।

'न्यायमूर्ति ने कहा कि यदि राज्यपाल को विधेयक रोकने की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त है तो धन विधेयक को भी तुरंत रोका जा सकता है। वह धन विधेयक को तुरंत रोक सकते हैं।' इस पर प्रसिद्ध अभिभाषक हरीश साल्वे ने उत्तर दिया कि वह ऐसा कर सकते हैं। साल्वे ने कहा कि अगर कोई अनुच्छेद 200 की स्पष्ट भाषा को बिना किसी पूर्वधारणा के पढ़े तो यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्यपाल किसी विधेयक को आसानी से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 200 का मूल प्रावधान यह नहीं कहता कि राज्यपाल धन विधेयक को रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम जो कर रहे हैं, वह यह है कि हम प्रावधान के बाहर से शब्द चुन रहे हैं और उन्हें प्रावधान से जोड़ रहे हैं। क्योंकि, हमें लगता है कि कुछ सीमाएं होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोकना राज्यपाल के पास स्वीकृति देने, विधानसभा को वापस भेजने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखने के अलावा चौथा विकल्प है।

इस पर न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने फिर पूछा कि आप इस बात को कैसे संतुलित करते हैं कि मूल प्रावधान के तहत राज्यपाल द्वारा धन विधेयक को शुरू में ही अस्वीकार किया जा सकता है! वह विधेयक को

तभी लौटा सकते हैं जब वह धन विधेयक न हो। आप इसे कैसे संतुलित करते हैं! इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अनुच्छेद 207 में इसका उत्तर है। सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट करते हुए कहा कि अनुच्छेद 207 के अनुसार, धन विधेयक केवल राज्यपाल के प्रस्ताव पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए राज्यपाल द्वारा धन विधेयक को रोकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यह राज्यपाल की अनुशंसा पर ही प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, साल्वे ने कहा कि ऐसी स्थिति भी हो सकती है, जब विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक राज्यपाल द्वारा अनुशंसित संस्करण से भिन्न हो। उन्होंने कहा कि यदि अंततः स्वीकृत किया गया प्रस्ताव राज्यपाल द्वारा अनुशंसित संस्करण से मेल नहीं खाता है तो राज्यपाल स्वीकृति रोक सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वह इस तर्क का परीक्षण काल्पनिक स्थितियों के आधार पर कर रहे हैं।

हरीश साल्वे ने कहा कि चूंकि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 207 के रूप में धन विधेयक के संबंध में एक सुरक्षा कवच जोड़ा है, इसलिए उन्होंने धन विधेयकों पर चौथा विकल्प (रोकना) लागू करना जरूरी नहीं समझा होगा। श्री हरिष साल्वे ने कहा कि यदि संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के विकल्पों पर कोई सीमाएं नहीं लगाईं तो व्याख्या के जरिए ऐसी सीमाएं नहीं जोड़ी जा सकतीं। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा तय करने के भी खिलाफ तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई। योजना के पीछे राजनीतिक प्रक्रिया होती है। हम पन्द्रह दिनों में इसे पूरा कर लेते हैं। लेकिन, कुछ मामलों में इसमें 6 महीने लग जाते हैं। यह कोई छुपकर बैठकर निर्णय लेने जैसा नहीं हो सकता।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद धारण करते हैं। हमें यह समझना होगा कि यह संविधान के अंतर्गत है। वह वस्तुतः अपनी इच्छा पर ही पद धारण करते हैं। एक अर्थ में, वह संघ और राज्य के बीच संवाद का माध्यम हैं। ऐसे में यह मानना कठिन है कि जब संघ विधेयक को स्वीकार नहीं करता और राज्यपाल उसे रोक लेते हैं तो यह मानना भी कठिन होगा कि संघ की कोई भूमिका नहीं है। संविधान इसी तरह काम करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि न्यायालय इस बात की समीक्षा नहीं कर सकता कि राज्यपाल ने अपनी सहमति क्यों नहीं रोकी। यदि प्रावधान में कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं हैं तो ऐसे कोई न्यायिक रूप से प्रबंधकीय मानक नहीं हैं, जिनके आधार पर शक्ति के प्रयोग की समीक्षा की जा सके। मुख्य न्याधिपति के इस स्पष्ट प्रश्न कि 'क्या न्यायालय राज्यपाल से पूछ सकता है कि वह आदेश क्यों रोक रहे हैं? के उत्तर में साल्वे ने जोरदार तरीके से 'नहीं' कहा। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट नीरा जे किशन कौल और मनिंदर सिंह ने भी केंद्र सरकार की दलीलों का समर्थन करते हुए तर्क दिए।

(शेष अगले कॉलम में)

साहित्य

विवेक कुमार साव

लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में शोधार्थी है।

ताजमहल का टेंडर- लाल फीताशाही का सच

नाटककार अजय शुक्ला के दिमाग में ये ख्याल कौंधा कि अगर आज के ज़माने में शाहजहाँ ताजमहल बनवाने की सोचे तो क्या होगा? बस, ये सवाल ही काफी था कि उनकी कलम अपने आप चल पड़ी। पात्र जैसे कहीं से अपने आप ही उतर आए, शाहजहाँ को छोड़कर बाकी सब यथार्थ, हमारे समाज से ही जो इस मुल्क की सड़कों, दफ्तरों, तमाम तंत्रों और टेंडर की फाइलों में खुलकर साँस लेते हैं। हालांकि, शाहजहाँ का नाम इस संदर्भ में मुगल बादशाह शाहजहाँ से प्रेरित है, किंतु केवल नाम का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें औरंगजेब नामक पात्र का भी उल्लेख है, जो इतिहास से लिया गया प्रतीत होता है, परंतु वह भी केवल नाम का उपयोग किया गया है।

इस नाटक का प्रथम प्रकाशन अक्टूबर 1998 में दिल्ली के प्रकाशन संस्थान द्वारा किया गया। हालांकि, साल 1993 में नाटककार ने इस नाटक को लिख लिया, किंतु इसका मंचन पाँच साल बाद ही हो पाया। उस दौरान निर्देशक नाक-भौं सिकोड़ते, कुछ कहते - ये ऐतिहासिक है कि सामाजिक?, कुछ और बुदबुदाते कि शाहजहाँ आज ताजमहल क्यों बनवाएगा? इस विषय में अजय शुक्ला खुद लिखते हैं कि जिस भी निर्देशक को नाटक पढ़ने को देता वह बड़ी रोनी-सी सूरत बनाकर लौटा देता। मगर 1998 में एन.एस.डी. रेपेर्टरी ने इसे मंच पर उतारा, और फिर क्या, ये नाटक तो जैसे देशभर में मशहूर हो गया। देश-विदेश के कई भाषाओं में अनुवाद, साथ ही विदेशों में भी मंचन। हम देखते हैं कि तीन दशक बाद भी ये उतना ही ज़िंदा है, इसलिए भी क्योंकि ये नाटक भ्रष्टाचार की उस नफ़स को पकड़ता है, जो इस मुल्क को कमजोर कर रही है। नाटक के शुरुआत में अजय शुक्ला इस नाटक को हास्य-व्यंग्य नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखते हैं। कहीं न कहीं वे यह सही ही कहते हैं।

इस नाटक को पढ़कर हम हँसते हैं, इस पर कई चर्चाएँ करते हैं। मोहन राकेश सम्मान से यह कृति सम्मानित है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, और आधुनिक भारत के श्रेष्ठ नाटकों में शुमार है। किंतु, जब हम इसे ऑफिस, घर, क्लासरूम या पुस्तकालय में पढ़कर या मंचों पर इसे देखकर बाहर कदम रखते हैं, तो वही टेंडर, वही रिश्वत, वही सिस्टम हमारे सामने होता है। इसकी लोकप्रियता नाटककार, पाठक या निर्देशक को सुख दे या दुख, यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है ; जैसा कि अदम गोंडवी ने अपने समय में गजल लिख कर उठाया था - जो उलझकर रह गई है फ़ाइलों के जाल में, गाँव तक वह रौशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, रमसुधी की झोंपड़ी सरपंच की चौपाल में।

नाटक की कहानी इस उपज पर टिकी है कि मुग़ल बादशाह शाहजहाँ, अचानक बीसवीं सदी पर दस्तक देते हैं, और ताजमहल बनवाने की इच्छा जाहिर करते हैं। मगर हम पाते हैं कि इन सबके इर्द-गिर्द सब कुछ आधुनिक, वही सरकारी दफ्तरों की फाइलें, रिश्वत की भेंट चढ़ते हुए अफसर, कुर्सी पर बैठकर सियासत की चालें चलते नेता। हर कदम पर टालमटोल और शाहजहाँ का सपना, जो भ्रष्ट नेताओं व अफसरों की भूलभुलैया में फंसकर रह जाता है। नाटक में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि पात्रों की बात-चीत पढ़कर ही हमारे आस-पड़ोस के कथित सम्मानित लोगों के चेहरे याद आ जाते हैं। स्टेट के चीफ इंजीनियर श्रीमान गुप्ता जी सुधीर को कहते हैं - हाँ, वाकई में बहुत बड़ा खेल है। ठीक से खेला जाए तो अरबों में जा सकता है। जवाब में सुधीर उत्साहपूर्वक कहता है - यानी कि अब तो किस्मत खुल गयी सर जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगा है, सर खुल गई किस्मत। यह संवाद व्यवस्था की विसंगतियों को बेहद सहज ढंग से उभारता है। जब सिस्टम चलाने वाला ही इसे खेल मानकर खुद उसमें लिप्त हो जाए, तो भ्रष्टाचार की गहरी जड़ें बन जाती हैं।

चीफ इंजीनियर गुप्ता जी के नेतृत्व में ताजमहल का सपना साकार करने का प्रोजेक्ट शुरू तो हुआ, मगर टेंडर की सूचना जारी करने में पच्चीस वर्ष बीत गए। इन वर्षों में तंत्र के सारे शोषक अपने-अपने लाभ लेने में मशगूल रहें। कॉर्पोरेशन से लेकर सिर पर छत तक, सब कुछ बनवा लिया, मगर ताजमहल? वो तो बस कागजों में ही उभरता रहा, बनने से कोसों दूर। जिस दिन टेंडर की सूचना निकलने की बारी आयी, गुप्ता जी शाहजहाँ को ये खुशखबरी सुनाने निकले ; मगर वहाँ पहुँचकर देखा तो शाहजहाँ की रूह कब की दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। नाटक के अंत में स्टेट चीफ इंजीनियर, सुधीर से कहता है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सुन लो। वक्त गया बात गई पर हम नहीं जाएँगे। फिर कोई ताज का ख्वाब देखेगा, तब हम फिर बुलाए जाएँगे, तब ये फाइल फिर काम आएगी। समझ गए। चलो अब यहाँ से चलते हैं। नाटक का व्यंग्य आज के सरकारी तंत्र की कमियों पर है। शाहजहाँ के पुराने दौर की नजर से देखने पर यह और भी गहरा लगता है। हँसी-मजाक व व्यंग्य के बीच नाटक उस निराशा को उजागर करता है, जो स्वार्थी लोगों ने आज़ादी के बाद के भारत में फैलाई है। नाटक के अंत में चीफ इंजीनियर की बातों से यह साफ झलकता है कि ताजमहल जैसा टेंडर आज बिक रहा है, कल भी बिकेगा, और सम्भवतः यों ही भविष्य में भी बिके, क्योंकि इस मुल्क में भ्रष्टाचार का बाजार सूना होता तो नहीं दिख रहा। फिर भी, कहीं न कहीं दिल में एक उम्मीद है कि शायद कोई सुबह आए, जब ये सब बदल जाए। नाटक के पन्ने पलटते-पलटते आखिर में अदम गोंडवी का लहजा फिर दिल में गूँज उठता है, मानो नाटककार भी हम सभी से कह रहे हों -

जिस्म क्या है, रुह तक सब कुछ खुलासा देखिए।
आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए।
जो बदल सकती है इस दुनिया के मौसम का मिज़ाज,
उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए।
जल रहा है देश, यह बहला रही है क़ौम को,
किस तरह अश्लील है संसद की भाषा देखिए।

पर्यावरण नीति

राज कुमार सिन्हा

लेखक पर्यावरण मामलों के जानकार हैं।

पर्यावरणीय मंजूरी विवाद की जमीनी स्थिति

मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अंतर्गत अधिसूचित किया है, जिसमें नई परियोजनाओं या गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध और निषेध लगाए गए हैं, मौजूदा परियोजनाओं और गतिविधियों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करना है।

मध्यप्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सिया) की कार्यशैली को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मई 2025 में, सिया ने एक दिन में ही 450 परियोजनाओं को मंजूरी देकर स्वीकृत कर दिया गया था। जबकि आवश्यकता अनुसार साझी बैठक बुलाना अनिवार्य था। इस प्रक्रिया में बैठक आयोजित नहीं की गई, फाइलें जानबूझकर लंबित रखी गईं, और समय सीमा समाप्त होने पर स्वीकृति अपने आप मान ली गई,जो नियमों का उल्लंघन है।इसमें 200 से अधिक परियोजनाएं खनन विभाग से संबंधित थीं, जिसमें भ्रष्टाचार की गंभीर आशंका है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अनुसार, पर्यावरणीय मंजूरी के लिए संबंधित प्राधिकरण की सामूहिक बैठक आवश्यक है। यह नियम पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। तकनीकी मूल्यांकन, जन-सुनवाई जैसी प्रक्रियाओं की अनदेखी हुई। कई मामलों में खनिज की मात्रा या नाम तक बदल दिए गए ताकि गैरकानूनी कृत्यों को कानूनी रूप दिया जा सके। आरोप है कि इस पूरा मामला खनन माफिया और दलालों को फायदा पहुंचाना था। अधिकारियों ने अनुमति प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सिया की स्वायत्तता कमजोर करने का प्रयास किया गया है। अन्य परियोजनाओं की मंजूरी पर भी विवाद उठी-जब सहमति से ये मंजूरियां दी गईं, तब सदस्य सचिव ने असहमति जताई और प्रक्रिया को अवैध करार दिया। 28 मार्च से 21 अप्रैल 2025 तक सिया में कोई बैठक नहीं हुई, सैकड़ों फाइलें लंबित रहीं। अप्रैल-मई 2025 में केवल तीन बैठकें हुई-लेकिन इनमें भी अधिकांश स्वीकृतियां सदस्य सचिव ने अकेले दी।

सिया के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान ने इन फर्जी मंजूरियों को उजागर किया, कई बार बैठक बुलाने का अनुरोध किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया को गैरकानूनी बताया। साथ ही एफआईआर दर्ज करने की मांग की। चेयरमैन एसएनएस चौहान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को दर किनार कर 237 परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृतियां दें दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सिया की सदस्य सचिव उमा महेश्वर और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत कोठारी ने मिलकर प्राधिकरण की बैठकों में देरी की, ताकि खनन माफियाओं को फायदा पहुंचाया जा सके। आरोप है कि इसके लिए सिया की अनिवार्य मूल्यांकन प्रक्रिया को भी दरकिनार कर कई प्रोजेक्ट्स को बिना अधिकार स्वीकृति दे दी। 24 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव-प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया। यह नोटिस 237 अवैध पर्यावरणीय मंजूरियों को लेकर जारी किया गया था, जहां सदस्य सचिव द्वारा सिया को बायपास कर स्वीकृतियां दी गई थी। कोर्ट ने पूछा कि ये मंजूरियां बिना सिया की बैठक के कैसे दी गईं, और उनसे दो सप्ताह में जवाब मांगा गया। इस मामले पर विगत सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बहुत गंभीर माना और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि आईएएस अधिकारी पर्यावरण स्वीकृति जारी करेंगे, तो फिर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण की स्वतंत्र संस्था होने का क्या मतलब रह जाएगा?

मध्य प्रदेश राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत अधिसूचित किया है, जिसमें नई परियोजनाओं या गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध और निषेध लगाए गए हैं, मौजूदा परियोजनाओं और गतिविधियों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करना है।

अधिसूचना के तहत, कुछ नई परियोजनाओं, मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण के लिए, उनके पर्यावरणीय प्रभाव की क्षमता के आधार पर, पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। अधिसूचना की अनुसूची में श्रेणी 'क' के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के लिए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक है जबकि श्रेणी 'ख' के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए, गतिविधियों की सीमा के आधार पर, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से मंजूरी आवश्यक है। अधिसूचना में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने एक राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन प्राधिकरण (सिया) के गठन का प्रावधान है। सिया की सहायता के लिए, एक राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) का गठन किया गया है। विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति परियोजनाओं की जांच करेगी और पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने पर निर्णय लेने हेतु अपनी सिफ़ारिशें सिया को भेजेगी।

पर्यावरण आंकलन अधिसूचना को पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत सबसे पहले 1994 में जारी किया गया था। इसके पहले यह कार्य महज प्रशासनिक जरूरत होता था। लेकिन 27 जनवरी 1994 में पर्यावरण प्रभाव नोटीफिकेशन के जरिये एक विस्तृत प्रक्रिया शुरू किया गया।इस नोटीफिकेशन के अन्तर्गत 32 औधोगिक एवं विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया। जिसमें बङेबांध, माइंस, एयरपोर्ट, हाइवे,समुद्र तट पर तेल एवं गैस उत्पादन, पेट्रोलियम रिफाइनरी, कीटनाशक उधोग, रसायनिक खाद, धातु उधोग, थर्मल पावर प्लांट, परमाणु उर्जा परियोजना आदि शामिल है। परियोजनाओं को एक विस्तृत प्रकिया से गुजरना आवश्यक बनाया गया। जिसके तहत पर्यावरण प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट (ई.आई.ए) तैयार कर सार्वजनिक करना एवं जन सुनवाई महत्वपूर्ण माना गया। ई.आई.ए रिपोर्ट अंग्रेजी तथा प्रादेशिक और स्थानिय भाषा में जिला मजिस्ट्रेट, पंचायत व जिला परिषद, जिला उधोग कार्यालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सभी विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का केवल सही- सही आंकलन ही न हो बल्कि इस आंकलन प्रक्रिया में प्रभावित समुदायों का मत भी लिया जाए और उसी के आधार पर परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी देना या नहीं देने का फैसला लिया जाए। इस अधिसूचना के अंतर्गत ही प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरणीय जन सुनवाई जैसा महत्वपूर्ण प्रावधान रखा गया है।

किसी भी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसके प्रभावों को पैनी नजर से आंकने और जांचने के रास्ते भी खुले और निर्णय प्रकिया में जनता की भूमिका भी बढी। इस प्रकिया में परियोजना चार चरणों से गुजरती है। जब परियोजना निर्माता आवेदन करता है, उसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्रतीक्षारत अवस्था कहते हैं।इसके बाद एक विशेषज्ञ आकलन समिति द्वारा परियोजना की छानबीन की जाती है। छानबीन के अन्तर्गत पर्यावरण प्रभाव आंकलन हेतु बिंदु (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) तैयार किए जाते हैं। इसी के साथ परियोजना टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्वीकृत अवस्था में आ जाती है।पर्यावरण प्रभाव आंकलन का मसौदा तैयार होने के बाद जन सुनवाई आयोजित की जाती है और उसके बाद पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना को अंतिम रूप दिया जाता है। ये सारे चरण पूरे होने के बाद रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है। यह अवस्था पर्यावरण मंजूरी प्रतीक्षारत अवस्था है। इसके उपरांत विशेषज्ञ आकलन समिति द्वारा सर्बंधित दस्तावेजों की छानबीन की जाती है और परियोजना को स्वीकृत या ख़ारिज की करने की सिफारिश करती है। एक बार पर्यावरण मंजूरी मिल जाने के बाद परियोजना पर्यावरण मंजूरी अवस्था में आ जाती है।पूंजी एवं कम्पनीयों के सामने झुकने वाली सरकार की मंशा विपरित होने के कारण 1994 से 2006 तक 12 सालों में 13 बार संशोधन किया गया। 14 सितम्बर 2006 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1994 के नोटीफिकेशन को बदल कर पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्रकिया 2006 बनाया गया। यह व्यवस्था भी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक की मदद से चलाए गए पर्यावरण प्रबंधन दक्षता विकास कार्यक्रम के आधार पर लाया गया। जिसमें कम्पनियों द्वारा परियोजना को स्वीकृति देने की प्रकिया को शीघ्र और सरकारी नियंत्रण को सरल करने जैसे सुझाव को शामिल कर लिया गया।जबकि स्वीकृति प्रकिया में शर्तो की मानिटरिंग तथा शर्तो की कार्य योजना महत्वपूर्ण है। लेकिन 2006 का नोटिफिकेशन अधिक जोर नहीं देता है। केवल इतना ही कहा गया है कि छह मासिक प्रतिवेदन देना होगा। प्रक्रिया कमजोर करने के बावजूद लोग आज भी उस जन सुनवाई में विरोध करने जाते हैं।

किसी भी औद्योगिक, खनन, पावर प्लांट, बांध या बुनियादी ढाचे की परियोजना से पर्यावरण को कितना नुकसान होगा, उसका मूल्यांकन किया जाए और नुकसान को कम करने के लिए शर्तें लगाई जाएं। लेकिन व्यवहार में अक्सर यह प्रक्रिया जनहित से ज्यादा कॉर्पोरेट हितों की ओर झुकी हुई दिखती है। कानून कहता है कि प्रभावित लोगों से जन-सुनवाई करनी होगी। हकीकत यह है कि ग्रामीणों, आदिवासियों और अन्य लोगों की राय को या तो रिकॉर्ड में ही बदल दिया जाता है या दबाव डालकर समर्थन दिखा दिया जाता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट अक्सर प्रोजेक्ट प्रायोजक की कंसल्टेंसी एजेंसियां बनाती हैं। रिपोर्टें में प्रायः कॉपी-पेस्ट, अधूरी या झूठी होती हैं-नदी, वन्यजीव, भूजल, प्रदूषण पर सही डेटा ही नहीं होता। कई बार परियोजना को कम नुकसानदायक दिखाने के लिए जानबूझकर आंकड़े घटाए-बढ़ाए जाते हैं।मंजूरी मिलने के बाद कंपनियां जो पर्यावरणीय शर्तें मानने का वादा करती हैं (जैसे- पेड़ लगाना, धूल नियंत्रण, नदी संरक्षण), उनकी निगरानी शायद ही कभी होती है।

श्री सांवरिया सेठ मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ, निकली भव्य कलश यात्रा

आयोजन स्वर्गीय मुरली उपाध्याय को एक अनूठी श्रद्धांजलि है

धार। श्री सांवरिया सेठ मंदिर, त्रिमूर्ति नगर, धार में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की स्मृति को समर्पित है, जिसने अपने जीवन को धर्म और सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। यह कथा स्वर्गीय मुरली उपाध्याय की याद में आयोजित की जा रही है, जो पवार वंश की आराध्य देवी, माँ गढ़ कालिका के पुजारी थे। उनका आकस्मिक निधन शहर के लिए एक बड़ी क्षति थी, क्योंकि उनकी पहचान केवल एक पुजारी के रूप में नहीं, बल्कि एक धार्मिक और लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में थी।

एक यादगार श्रद्धांजलि: आध्यात्म और श्रद्धा का संगम

यह आयोजन स्वर्गीय मरली उपाध्याय को एक अनूठी श्रद्धांजलि है, जिसमें आध्यात्म और श्रद्धा का संगम देखने को मिला। कथा के पहले दिन, त्रिमूर्ति नगर में एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो श्रद्धा और भक्ति के रंग में डूबी हुई थी। पीले वस्त्र धारण किए हुए महिलाएं सिर पर कलश रखकर भक्ति गीतों पर मंत्रमुग्ध होकर नृत्य कर रही थीं। शहर के गणमान्य नागरिकों और

त्रिमूर्ति नगर के निवासियों ने विभिन्न वेशभूषा में इस शोभायात्रा में भाग लिया, जिससे यह यात्रा और भी मनमोहक हो गई। शोभायात्रा का जगह-जगह पर फूलों की वर्षा और पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

यात्रा के दौरान, कथावाचक आचार्य मनीष दुबे को एक सुसज्जित रथ में विराजमान किया गया, जिनका हर कदम पर सम्मान किया गया। इस यात्रा में स्वर्गीय मुरली उपाध्याय के पुत्र उत्कर्ष उपाध्याय और उनकी पत्नी ने सिर पर भागवत पोथी धारण कर अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। उनके परिवार के अन्य सदस्य भी इस शोभायात्रा में शामिल हुए, जो दर्शाता है कि यह आयोजन सिर्फ एक सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक पारिवारिक श्रद्धांजलि भी है।

भागवत कथा का महत्व और आयोजन का उद्देश्य...

दोपहर 2 बजे कथा का शुभारंभ सांवरिया सेठ मंदिर में हुआ, जहां भागवत महापुराण का विधि-विधान से पूजन और पितृगणों का आह्वान किया गया। कथा के पहले दिन, आचार्य मनीष दुबे ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह महापुराण न केवल भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता है, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और धर्म के सिद्धांतों को भी सिखाता है।

यह आयोजन स्वर्गीय मुरली उपाध्याय मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है और इसका सीधा प्रसारण विशाल स्टूडियो द्वारा किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में श्री सांवरिया सेठ मंदिर के ट्रस्टी, स्वयं प्रकाश सोनी, 18 महापुराण समिति के प्रमुख, अशोक मनोहर जोशी, और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस आयोजन का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक कथा सुनाना नहीं, बल्कि उन मूल्यों और सिद्धांतों को जीवित रखना है, जिनके लिए स्वर्गीय मुरली उपाध्याय जाने जाते थे। यह कथा वास्तव में एक श्रद्धांजलि है - एक ऐसे व्यक्ति को, जिन्होंने अल्पायु में ही समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। यह आयोजन उनकी स्मृति को अमर बनाएगा और धर्म के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाता रहेगा।

जैन धर्म के नौवें तीर्थंकर भगवान पुष्पदंतस्वामी का मोक्ष कल्याणक पर्व मनाया

दिगंबर जैन समाज के पर्यूषण का चतुर्थ दिन

धार। दिगम्बर जैन समाज के पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व के चतुर्थ दिवस पर नौवें तीर्थंकर भगवान पुष्प दंत स्वामी का मोक्ष कल्याणक लाडू चढ़ाकर मनाया गया। लाडू चढ़ाने का सौभाग्य नरेशकुमार श्रेणिक कुमार श्रेयांश आदित्य गंगवाल परिवार को मिला। पर्यूषण पर्व का आज चौथा दिन उत्तम शौच धर्म का मनाया गया। प्रातः अभिषेक शांति धारा परम पूज्य गुरुदेव विभंजन सागर जी ससंघ के सानिध्य में हुई। तत्पश्चात गुरुदेव की दिव्या देशना उत्तम शौचधर्म पर हुई। गुरुदेव ने प्रवचन में कहां कि शौचधर्म आत्मा का ही स्वभाव है कारण कि शौच धर्म अंतरंग आत्मा से लोभादि कषायों के अलग हो जाने पर ही प्रगट होता है। लोभादि कषायें पर पदार्थो की चाह रूप प्राप्ति की इच्छा से उत्पन्न होती हैं, इसलिये ये परभाव हैं। सो इन परभावोंके अभाव होने पर जो आत्मा का स्वभाव प्रगट होना सो निश्चय शौच धर्म है।

व्यक्ति को लोभ नहीं करना

चाहिए जिसके पास सौ रुपए है उसे हजार चाहिए जिसके पास हजार है उसको लाख चाहिए। जो है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। लोभ प्रवृत्ति को जैन धर्म में पाप बताया है। मीडिया प्रभारी संजय गंगवाल ने बताया कि पर्युषण पर्व में पांच दिवसीय और दस दिवसीय निर्जल उपवास की तपस्या भी चल रही है!

सभी भक्त भक्ति भाव से पूजा पाठ तप आराधना कर समवशरण मंडल विधान पर पूजन कर आराधना कर धर्म लाभ विधानाचार्य भरतजी शास्त्री और संगीतकार दीपेश जैन के सानिध्य में ले रहे हैं। समाज के अध्यक्ष श्रेणिकजी गंगवाल ने बताया कि कल संध्याकालीन समोसरण विधान की आरती,पंच परमेष्ठी की आरती तत्पश्चात गुरुदेव की आरती के साथ ही धार्मिक तंबोला का कार्यक्रम हुआ।

कार्यक्रम बहुत ही शानदार हुआ जिसमें गुरुदेव द्वारा प्रश्न भी पूछे गए। विजेताओं को पुरस्कार दिया गया।

दीनदयाल रसोई फिर शुरू, विश्वकर्मा समाज समिति को जिम्मेदारी

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने फीता काटकर किया शुभारंभ

बैतूल। जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाली दीनदयाल रसोई का पुनः संचालन शुरू हो गया है। रविवार सुबह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने फीता

काटकर इसका शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं मजदूरों को नाश्ता परोसा। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष पार्वती बारस्कर, भाजपा नेता आनंद प्रजापति और महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ममता मालवीय उपस्थित रहीं। समाज के संयोजक बलवीर मालवीय, सीएमओ सतीश मटसेनिया के साथ कई पार्षद, व्यापारी और समाजसेवी भी मौजूद रहे। विश्वकर्मा समाज समिति को इस बार रसोई के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। बैतूल में दीनदयाल रसोई की शुरुआत 2014 में हेमंत खंडेलवाल ने विधायक रहते हुए की थी। स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों और व्यापारियों का इसमें सहयोग रहा। इसकी सफलता के बाद 2017 से सरकार ने इसे पूरे प्रदेश में योजना के रूप में लागू किया। खंडेलवाल ने कहा कि समाज के सहयोग से यह रसोई निरंतर चलती रहेगी। मजदूर वर्ग की सुविधा के लिए सुबह का नाश्ता भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने परिजनों के जन्मदिन और पुण्यतिथि जैसे अवसरों पर इस रसोई में भोजन कराकर मनाएं।

साक्षरता की अलख जगाने साक्षरता रथ का आगमन

बैतूल/आमला। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला साक्षरता मिशन बैतूल का साक्षरता रथ आमला पहुंचा। जिसकी अगवानी विकास खण्ड स्रोत समन्वयक मनीष धोटे एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र साहू के द्वारा की गई। इस रथ के माध्यम से 15 वर्ष या 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के ऐसे वयस्क, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा पूर्ण नहीं किया है, जिन्हें उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षर किया जाना है। इसके लिए जिला शिक्षा केंद्र की पहल पर यह रथ शिक्षा की अलख जगाने हेतु जिले के विभिन्न विकास खण्डों से होते हुए आज आमला पहुंचा, जिसे विकास खण्ड आमला के विभिन्न ग्रामों में भ्रमण हेतु अधिकारियों द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप जनपद शिक्षा केंद्र आमला का समस्त स्टाफ व सांदीपनी उच्च माध्य विद्यालय आमला के शिक्षक व गणमान्य गण उपस्थित थे। विकास खण्ड स्रोत समन्वयक मनीष धोटे ने अपने संबोधन में कहा कि निश्चित ही इस रथ के माध्यम से 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों में जागरूकता आएगी व उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत विकास खण्ड के समस्त विभिन्न ग्रामों में अक्षर सैनिकों के माध्यम से चलाए जा रहे। सामाजिक चेतना केंद्रों से जुड़कर वे अपनी पढ़ाई पूर्ण करेंगे। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी धीरेंद्र साहू के द्वारा बताया गया कि इस साक्षरता रथ के माध्यम से जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा जो निरक्षरों को जागरूक करने के लिए चलाई जा रही। यह एक अनूठी पहल है, यह पहल निश्चित ही 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निरक्षरों को साक्षर करने में मिल का पत्थर साबित होगी। तत्पश्चात रथ को आगे के लिए रवाना किया गया।

खेल दिवस पर शासकीय कन्या उमावि ने की सहभागिता

बैतूल। नगर परिषद बैतूल बाजार द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर विभिन्न खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूल बाजार की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विद्यालय की छात्राओं ने कबड्डी, दौड़ प्रतियोगिता तथा अन्य खेलों में हिस्सा लिया। नगर परिषद द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किए गए।

ड्राइंग-डिजाइन में बार-बार बदलाव से हुई देरी, अब एग्रीमेंट होते ही शुरू होगा काम

गंज मंडी कॉम्पलेक्स का एक बार फिर टेंडर फाइनल

बैतूल। लागत बढने और बार-बार ड्राइंग डिजाइन बदलने के चलते अधूरे पड़े गंज मंडी कॉम्प्लेक्स के पूरे होने की आस एक बार फिर जागी है। हालांकि बैतूल जिले का यह इकलौता मंडी कॉम्प्लेक्स है, जिसके निर्माण में हर स्तर पर रुकावटें आई हैं, चाहे वह लागत बढने की हो या फिर ड्राइंग डिजाइन बदलने की या फिर राजनीतिक उलटफेर हों, हर स्तर पर रुकावटों का सामना कर रहे इस अधूरे मंडी कॉम्प्लेक्स से सबसे ज्यादा नुकसान उन व्यापारियों का हुआ है जो गंज मंडी कॉम्प्लेक्स के पूरा होने की लगभग 11 साल से आस लगाए बैठे हैं। दरअसल गंज में बनने वाला बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स का निर्माण 11 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन यह बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स अभी भी अधूरा ही है। जानकारों द्वारा इसके पीछे मुख्य कारण, पिछले 11 वर्षों में इस कॉम्प्लेक्स की ड्राइंग व डिजाइन चार बार बदली जाना बताया जा रहा है। जब 11 वर्ष पूर्व मंडी कॉम्प्लेक्स निर्माण की योजना बनाई थी, तब इसकी लागत करीब साढ़े नौ करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर दोगुनी तक पहुंच गई है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि इस काम्प्लेक्स के लिए नपा को चौथी बार ड्राइंग डिजाइन बदलना पड़ा है। काम्प्लेक्स की बार-बार ड्राइंग डिजाइन बदलने से पुराने ठेकेदार ने बीच में ही काम छोड़ दिया था।

एग्रीमेंट होते ही शुरू होगा कॉम्प्लेक्स का काम .....

बताया जा रहा है कि भोपाल की एक कंपनी को मंडी कॉम्प्लेक्स पूरा करने के लिए ठेका दिया गया है, टेंडर फाइनल हो गया है, अब एग्रीमेंट फाइनल होते ही मंडी कॉम्प्लेक्स का काम फिर से शुरू होगा। हालांकि अभी बारिश खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद काम शुरू करने की बात अधिकारियों द्वारा कहीं जा रही है। बता दे कि मंडी कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले वर्ष 2014 में 10 करोड़ 40 लाख रुपए की मंजूरी मिली थी, इसके बाद वर्ष 2017 से मंडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू हुआ था। लेकिन

2019 में ड्राइंग डिजाइन संशोधन करके दुकानें बढ़ाने की प्रक्रिया के कारण यह अटक गया। बाद में काम शुरू करने की बारी आई तो अधिक बजट की जरूरत होने और दोबारा बजट बढ़ाकर मंजूरी लेने के चक्कर में काम रुका रहा। अब एक फिर से टेंडर होने के बाद यह उम्मीद की जा रही है इस बात निर्माण पूरा होगा।

टीन शेड और तारपोलिन में लग रही दुकानें.....

जब से गंज मंडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू हुआ है तभी से गंज का बाजार बुरी तरह से अव्यवस्थित हो गया है। कॉम्पलेक्स में जिन व्यापारियों ने दुकानें ली हैं, वे फिलहाल अव्यवस्थित रूप से लंबे समय से व्यापार करने को मजबूर हैं, कोई तारपोलिन लगाकर तो कोई टीन की टपरी में अपनी दुकान संचालित कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब लंबा समय बीत जाने के बाद व्यापारियों के भी सब्र का बांध फूट रहा है। आक्रोशित व्यापारियों का कहना है कि कभी लागत बढ़ रही है, तो कभी ड्राइंग डिजाइन बदली जा रही है। कभी राजनीति अड़ंगा लगाया जा रहा है, लेकिन व्यापारियों की सुविधाओं को पूरी तरह से नजर अंदाज किया जा रहा है, इसलिए गंज के व्यापारी जनप्रतिनिधियों से भी कई बार मिलकर मंडी कॉम्प्लेक्स निर्माण पूरा करने की गुहार लगा चुके हैं।

कॉम्प्लेक्स अधूरा होने से अव्यवस्थित हुआ गंज बाजार ....

गौरतलब है कि गंज मंडी कॉम्पलेक्स में ऊपर दुकानें और बेसमेंट में पार्किंग निर्माण की प्लानिंग की गई थी, क्योंकि गंज में फिलहाल पार्किंग के लिए कहीं भी स्थान चिन्हित नहीं है, जिसके कारण पूरा गंज बाजार ही अव्यवस्थित हो गया है, यदि मंडी कॉम्पलेक्स पूरा होता तो कई गुमठियां सडकों से हट जाती, वहीं व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था भी हो जाती, लेकिन दुकानों के घटाने-बढ़ाने और लागत बढने के फेर में लंबा समय हो गया। इसके अलवा गंज मंडी कॉम्पलेक्स की जगह पर ही सब्जी बाजार भी लगा करता था जो अब सडक पर आ गया है, बाबू चौक गंज से लेकर कॉलेज चौक तक सडकों पर सब्जियों की दुकानें लगाई जाती हैं। साप्ताहिक सब्जी बाजार की प्लानिंग भी नगरपालिका लंबे समय से कर रही है, लेकिन कहीं जमीन अब तक फाइनल नहीं हो पाई है।

इनका कहना है -

बैतूल गंज मंडी कॉम्पलेक्स के लिए 15 करोड़ की लागत से कंस्ट्रक्शन का ठेका भोपाल की कंपनी को दिया गया है, टेंडर फाइनल हो गए हैं, एग्रीमेंट होते ही गंज मंडी कॉम्पलेक्स का काम शुरू करवाया जाएगा। इसका निर्माण जल्द से जल्द पूरा करवाया जाएगा।

- सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

विधायक डॉ. पंडाग्रे ने किया 6 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन

बैतूल/आमला। आमला-सारणी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने 6.33 करोड़ की लागत से बनने वाली महत्वपूर्ण सडक़ परियोजना का भूमिपूजन किया है। यह सड़क नागदेव मंदिर सोनतलाई से होते हुए बोपलवाड़ी मार्ग से बोरगांव तक जाएगी, जो क्षेत्रीय आवागमन और व्यापार के लिए बड़ी सहूलियत लेकर आएगी। इसी के साथ 1.11 करोड़ रुपये की लागत से कोंडरखापा मुख्य मार्ग से होते हुए समरतढाना मार्ग का भूमिपूजन भी किया गया। इन दोनों सडक़ों के निर्माण से ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्गों से सीधा संपर्क मिलेगा और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। विधायक डॉ. पंडाग्रे ने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास ही उनकी पहली प्राथमिकता है और जनता को हर सुविधा उपलब्ध कराना उनका संकल्प है। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों को बनाने का मैंने वादा किया था वह वादा आज पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के दौरे पर आया था तब ग्रामीणों को मैंने सडक़ का वादा किया था। सडक़ के लिए वर्षों से ग्रामीण परेशान थे। इसके आलावा बोपलवाडी की बिजली की समस्या को खत्म किया जाएगा। सर्वे करवाया जा चुका है, ग्राम में हर घर में बिजली होगी। सोनेगाँव के किसानो से बैराज निर्माण का वादा किया है, जिसे पूरा करवाया जाएगा। मंच से उतरकर विधायक श्री पंडाग्रे ने कार्यक्रम में आई सभी माता बहनो व ग्रामीणों से सीधे भेट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अंत में लोगों ने मिलकर क्षेत्र के चहुंमुखी विकास का संकल्प लिया। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रामकिशोर देशमुख, गणेश यादव, किशन सिंह रघुवंशी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष यदुराज सिंह रघुवंशी, जिला पंचायत प्रतिनिधि महेश मृस्कोले, रामचंद्र देशमुख सहित आसपास के ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने विधायक का स्वागत किया और विकास कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

किसानों के लिए सिंचाई परियोजना का आश्वासन

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष रामकिशोर देशमुख ने कहा कि विकास कार्यों की यह श्रृंखला केवल सडक़ों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में सिंचाई परियोजनाओं को भी गति दी जाएगी। विशेष रूप से बैराज निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। क्षेत्र में जल्द ही करोडो की लागत से बनने वाले बैराजो को स्वीकृति मिलने वाली है। जिसका भूमिपूजन भी आगामी कुछ माह के अंदर किया जाएगा। जिससे किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा मिले और खेती की उत्पादकता बढ़े।

प्रूफ रेंज में आदिवासी ग्राम नहीं होंगे विस्थापित

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मिले घोड़ाडोंगरी के पूर्व विधायक मंगल सिंह धुर्वे

बैतूल/भौंरा। प्रूफ रेंज विस्तार के विरोध और विस्थापन की आशंकाओं के बीच अब आदिवासी क्षेत्रों को बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। घोड़ाडोंगरी विधानसभा के पूर्व विधायक मंगल सिंह धुर्वे ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुलाकात कर घोड़ाडोंगरी विधानसभा के प्रभावित ग्रामों की चिंता उनसे साझा की। मंगल सिंह धुर्वे ने प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया कि प्रूफ रेंज विस्तार और नए फायरिंग रेंज निर्माण की खबरों ने ग्रामीणों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया है। इनमें विशेष रूप से टेमरामाल, टेमरा रैयत, खदारा, रामपुरमाल, मलाजपुर, चिचोली, चिखली, धप्पा, सेहरा, झारकुंड और खदडू गांव शामिल हैं। इन गांवों के लोग पिछले कई दिनों से विस्थापन की आशंका को लेकर आंदोलन और विरोध जता रहे हैं। मंगल सिंह धुर्वे की बात सुनने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि प्रूफ रेंज विस्तार निरस्त कराने की कोशिश करेंगे, और किसी भी गांव को

विस्थापन की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े ऐसा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इन गांवों की सुरक्षा और अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य स्तर पर इस मामले को गंभीरता से रखा जाएगा और ग्रामीणों के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि वे घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित ग्रामों के जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों प्रूफ रेंज विस्तार की खबरें सामने आने के बाद जिले में विरोध की लहर उठी थी। बैतूल, चिचोली, घोड़ाडोंगरी और आसपास के गांवों के हजारों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रैली निकाली थी और विस्थापन विरोधी ज्ञापन सौंपा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए पत्र ने इस विवाद को और गहरा दिया था। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि उनके गांव सुरक्षित रहेंगे।

प्रधानमंत्री की दिवंगत मॉ पर अशोभनीय टिप्पणी से महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन

जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने फूंका राहुल गांधी का पुतला

बैतूल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दिवंगत माता के लिए वोट अधिकार यात्रा के तहत बिहार में इंडी गठबंधन के नेताओ के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने अशोभनीय टिप्पणी से नाराज भाजपा महिला मोर्चा ने भारी संख्या में शामिल होकर जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन से रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए गंज बस स्टैण्ड के पास नव संचालित जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने राहूल गांधी का पूतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि बिहार में भाजपा और एनडीए के बढते जनाधार को देखकर कांग्रेस के नेता मानसिक संतूलन खो बैठे है प्रधानमंत्री की माता जी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी कांग्रेस के वास्तविक चेहरे को सामने लाने वाली है। श्री पंवार ने कहा कि नफरत की आग में जलने वाले इंडी गठबंधन के नेताओ का मौन प्रधानमंत्री जी की माता के अपमान पर बना हुआ है। यह सिर्फ

मोदी जी की माताजी का अपमान ही नही संपूर्ण मात्र शक्ति का अपमान है। इस अपमान से महिलाओ में आक्रोश है लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादवइ स अपमान को अपना मौन समर्थन दे रहे है। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ममता मालवी ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा शुरूआत से ही महिलाओं का अपमान करने वाली रही है। बिहार में जिस तरह से मोदी जी की माता जी के लिए टिप्पणी की गई वह सभ्य समाज में स्वीकार्य नही है। हार को सामने देखकर राहूल गांधी व इंडी गठबंधन के नेता बौखलाकर अनर्गल टिप्पणीयां कर रहे है। इसी टिप्पणी के आक्रोश में आज राहूल गांधी का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व सांसद ज्योति धुर्वे, जिला उपाध्यक्ष रश्मि साहू, इंद्रपाल पुण्डे, जिला मंत्री वर्षा गढेकर, जिला कार्यालय मंत्री कृष्णा गायकी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष हंसराज धुर्वे ,मंडल अध्यक्ष विकास मिश्रा, विक्रम वैद्य, नीतू पटेल, रिंकू सिनोटिया, नीतू गुप्ता, पुष्पा खाडे, मधु पाटनकर, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष भास्कर मगरदे, महेश राठौर, कैलाश धोटे, वरूण धोटे, पवन याव, नपाध्यक्ष पार्वती बारस्कर, आठनेर नपाध्यक्ष सुषमा जगताप,महिला मोर्चा जिला महामंत्री लाजवंती नागले, सुनिता देशमुख, वर्षा खाडे सहित महिला मोर्चा जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पार्षद, जनपद सदस्य सहित बडी संख्या में उपस्थित रही।

संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सब जेल मुलताई में स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित

बैतूल (निप्र)। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को सब जेल मुलताई में बंदियों में कुष्ठ रोग से संबंधित शंकाप्रद रोगियों की जांच के लिए शिविर आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज कुमार हुरमाड़े ने बताया कि शिविर में 103 बंदियों की जांच जिला स्तरीय कुष्ठ रोग दल के श्री राजेश मेहतो एवं श्री लिखीराम सागरे एनएमए द्वारा की गई, जिनमें से 13 बंदियों को चर्म रोग से संबंधित समस्या पाई गई, जिन्हें दवाईयां वितरित की गई। किसी भी बंदी में कुष्ठ रोग के लक्षण नहीं पाए गए। शिविर में कुष्ठ रोग से संबंधित जानकारियां प्रदाय की गई। शिविर में जेल फार्मासिस्ट श्री दीपक पंवार मौजूद रहे।

अधिकारियों द्वारा किया गया पेट्रोल पंप का औचक निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले के पेट्रोल पंपों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में अधिकारियों द्वारा सीहोर के लुनिया चौराहा स्थित वर्मा फ्यूलस एंड सर्विस पेट्रोल पंप का निरीक्षण कर जांच की गई। जांच के दौरान अंडरग्राउंड डीज़ल के टैंक मे भण्डारित 5,944 लीटर डीजल मे 10.5 सेमी पानी की मात्रा पायी गई और 04 प्रतिशत से अधिक अंतर तक की अनियमितता पाई गई। इसके साथ ही ऑनलाइन स्टॉक से डीजल के स्टॉक मे अंतर पाया गया। पेट्रोल पंप पर मुफ्त हवा, शौचालय, पेयजल, अग्नि शमन यन्त्र की वैधता भी समाप्त पाई गई। अधिकारियों द्वारा पेट्रोल पंप पर अनियमितताएं पाए जाने पर डीज़ल की मशीन को सील कर दिया गया है और पेट्रोल पंप से 5,45,081 रूपये मूल्य का 5,944 लीटर डीजल जब्त कर लिया गया है। यह कार्रवाई जिला अपूर्ती अधिकारी, नापतौल निरीक्षक एवं कनिष्ठ अपूर्ती अधिकारी द्वारा की गई।

राष्ट्रीय खेल दिवस पर कलेक्टर-एसपी ने टेबल टेनिस खेलकर खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित

सीहोर (निप्र)। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर चर्च ग्राउंड स्थित इंडोर हॉल परिसर में अनेक खेल गतिविधियां एवं कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बालागुरू के. और एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला ने खेल गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स सामग्री किट भी प्रदान की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए टेबल टेनिस भी खेला। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री बालागुरू के. तथा एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला ने कहा कि खेल केवल जीत-हार का नाम नहीं है, बल्कि खेल जीवन में अनुशासन, धैर्य और सहयोग की भावना का पाठ पढ़ाते हैं। खेलों से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक मजबूती भी आती है। उन्होंने कहा कि खेल व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उसे जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों और विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कलेक्टर और एसपी द्वारा टेबल टेनिस खेलने से खिलाड़ियों का जोश और भी दोगुना हो गया। इस अवसर पर सभी को खेल गतिविधियों से जुड़कर स्वयं को स्वस्थ बनाने की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर खेल अधिकारी श्रीमती रूबिका देवान, श्री मनोज कन्नौजिया, सूबेदार प्राची राजपूत सहित प्रशिक्षक एवं खिलाड़ी उपस्थित थे। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर इंडोर खेल परिसर के साथ ही जिलेभर में अनेक खेल गतिविधियां आयोजित की गईं।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाढ़ राहत, खोज एवं बचाव तकनीक विषय पर प्रशिक्षण सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को बाढ़ राहत, खोज एवं बचाव तकनीक विषय पर प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। जिसमें आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल से आए विशेषज्ञ द्वारा बाढ़ आने के कारण, बाढ़ आने की संभावना होने पर किए जाने वाले कार्य और बाढ़ आने पर बचाव कैसे करें! इसके बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि कई घण्टों से मूसलाधार बारिश होने या फिर विगत कुछ दिनों से लगातार बारिश होने पर बाढ़ आने की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में नदियों व बरसाती नाले से दूर रहना चाहिए। बाढ़ संभावित क्षेत्र में घर होने पर अति आवश्यक वस्तुएं व प्राथमिक किट तैयार रखनी चाहिए तथा किसी भी समय घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रशिक्षण में सर्पदंश, वज्रपात या आकाशीय बिजली गिरने, भवनों में आग लगने, भूकम्प आदि आपदाएं आने पर किस प्रकार त्वरित रूप से राहत और बचाव कार्य किए जाएं, कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए आदि के बारे में भी विस्तार से बताया गया। कार्यशाला में डिप्टी कलेक्टर, अधीक्षक भू-अभिलेख सहित अधिकारी, कर्मचारी और प्रतिभागी उपस्थित रहे।

सरेराह लड़की का हाथ पकड़ा, खींचकर ले जाने लगा

जबलपुर में छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों में पथराव, 4 थानों की पुलिस पहुंची

जबलपुर (नप्र)। जबलपुर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के बाद दो पक्ष आमने-सामने हो गए। आरोपी लड़की का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पत्थर चले। 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एक पक्ष ने आरोपी को पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान आरोपी पक्ष के लोग पुलिस से भिड़ गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस आरोपी को ले गई।

घटना बाबा टोला इलाके में शनिवार शाम की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद बाबा टोला इलाके के लोगों ने हनुमानताल थाने का घेराव कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में खुलेआम शराब, जुआ और स्मैक का धंधा चल रहा है। पुलिस को सख्त कदम उठाना चाहिए। वहीं, रविवार को कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को जेल भेज दिया है।

सरेराह लड़की का हाथ पकड़ा था- नाबालिग शनिवार शाम को कॉलेज से लौटते समय अपनी सहेलियों के साथ घर पैदल जा रही थी। इसी दौरान मोहम्मद समीर अंसारी उर्फ बब्लू खटीक ने उसका रास्ता रोक लिया। जबरन बात करने के लिए उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा। लड़की ने विरोध करते हुए किसी तरह हाथ छुड़ाया और घर पहुंची।

इसके बाद लड़की के परिवार के लोग मोहम्मद समीर के घर पहुंच गए। जहां दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ। विवाद की सूचना मिलते ही हनुमानताल, घमापुर, बेलबाग और गोहलपुर थानों का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। यहां लोगों को समझाइश गई। इस दौरान पुलिस की कुछ लोगों से झड़प हो गई।

समीर ने पोती का दुपट्टा पकड़कर खींचा

छेड़छाड़ पीड़िता की दादी ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब सिंधी कैंप से बाबा टोला के बीच लड़कियों के साथ छेड़खानी की घटना हुई हो। मोहम्मद समीर ने अपने दो दोस्तों के साथ तीनों ने लड़कियों का रास्ता रोका। समीर पोती का दुपट्टा पकड़कर जबरन सड़क से किनारे ले जाने लगा। लड़कियों ने विरोध करते हुए शोर मचाया, जिसके बाद वहां भीड़ जुट गई। इसके बाद आरोपी और उसके दोनों साथी मौके से फरार हो गए।

लड़की की दादी ने आरोप लगाया कि मोहम्मद समीर का पूरा परिवार अवैध कामों में लिप्त है। उनके घर से स्मैक, गांजा और शराब बेची जाती है।

छेड़खानी करने वाला गिरफ्तार

एएसपी जितेंद्र सिंह ने बताया, बाबा टोला में दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। विवाद को शांत करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद समीर के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल क्षेत्र में शांति है।

सुरेश पचौरी की पत्नी के रिटायरमेंट पार्टी में दिखे कमलनाथ

दिल्ली में हुए समारोह में सीएम डॉ. मोहन यादव और दिग्गज नेता भी रहे मौजूद

भोपाल (नप्र)। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सरकार गिरने को हुई बयानबाजी और ट्विटर वॉर के बीच पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी की पत्नी सुपर्णा पचौरी (आईएएस) के सेवानिवृत्ति समारोह में पूर्व सीएम कमलनाथ नजर आए।

दिल्ली के होटल अशोका में 28 अगस्त को हुए समारोह में पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, मप्र के सीएम डॉ. मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल, केन्द्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता प्रमोद कृष्णम, भोपाल सांसद आलोक शर्मा, होशंगाबाद सांसद चौधरी दर्शन सिंह सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण शामिल हुए। इस समारोह की तस्वीरें अब सामने आई हैं।

पिछले साल बीजेपी में शामिल हुए थे सुरेश पचौरी- कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने पिछले साल मार्च में लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी जॉइन कर ली थी। इसके बाद कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनपर हमले किए थे। लेकिन, सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी कांग्रेस नेताओं से अच्छे संबंध हैं। पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए प्रमोद कृष्णम और पूर्व सीएम कमलनाथ एक साथ दिखे।

पशुपालन विभाग में जॉइंट सेक्रेटरी से रिटायर हुई हैं पत्नी- सुरेश पचौरी की पत्नी सुपर्णा पचौरी केन्द्रीय पशुपालन मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुई हैं। वे वित्त सलाहकार भी रहीं हैं। कई महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी अहम भूमिका रही है।

उज्जैन में पुलिया से कार बही, बाढ़ में फंसे लोग

रायसेन में राहतगढ़ झरना फूटा; ग्वालियर-गुना समेत 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में भारी बारिश से नदी-नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियां पार कर रहे हैं। उज्जैन में कार सवार पुलिया से बह गए। कार झाड़ियों में फंस गई। वहां मौजूद लोगों ने कार सवारों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला।

उज्जैन में गंभीर डैम का एक गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम में तवा डैम के तीन गेट आज भी खुले हुए हैं। रायसेन में भारी बारिश के बाद राहतगढ़ वाटरफॉल 80 फीट ऊंचाई से गिर रहा है।

ग्वालियर-गुना समेत मध्यप्रदेश के 23 जिलों में रविवार को भारी बारिश का अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे में ढाई से साढ़े 4 इंच तक पानी गिर सकता है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, चंबल और सागर संभाग में भी तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश की चेतावनी दी है।

दो स्ट्रॉन्ग सिस्टम, इसलिए तेज बारिश का दौर- सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया- मध्यप्रदेश के बीचोंबीच से एक मानसून टर्फ गुजर रही है। वहीं, साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) की एक्टिविटी भी है। इस वजह से शनिवार को इंदौर समेत कई जिलों में तेज बारिश का दौर बना रहा।रविवार को भी सिस्टम का असर देखने को मिला।

इंदौर में 3 इंच से ज्यादा बारिश, खरगोन भी तरबतर

प्रदेश के निमाड़ में शनिवार को बादल जमकर बरसे। इंदौर में 3.1 इंच पानी गिर गया। वहीं, खरगोन में डेढ़ इंच बारिश हुई। गुना में आधा इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। ग्वालियर, पचमढ़ी, रतलाम, बालाघाट, हरदा, श्योपुर, मंदसौर, धार में भी हल्की बारिश का दौर जारी रहा। रात में भी कई जिले भीगे।

शाजापुर में तेज गरज-चमक के साथ बारिश

शाजापुर में रविवार दोपहर तेज गर्जन-चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। इससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 23 डिग्री रहा। मौसम विशेषज्ञ सत्येंद्र धनोतिया ने अगले दो दिन रुक-रुककर बारिश की संभावना जताई।

चिचोली में कबड्डी, दौड़, रस्साकसी खेल गतिविधियों का आयोजन

बैतूल (निप्र)। मेरा युवा भारत बैतूल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार और श्रीराम युवा विकास युवा मंडल गोधना के सहयोग से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को चिचोली ब्लाक के तपश्री ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें कबड्डी,दौड़, रस्साकसी प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर श्री अनिल सिंह कुशवाहा व नगर परिषद की उपाध्यक्ष वर्षा आवलेकर, विधायक प्रतिनिधि श्री उमेश पेठे, सीएमओ चिचोली श्री सैयद हुसैन, जिला युवा अधिकारी मेरा युवा भारत श्रीमती सुषमा गवली उपस्थित रही। कार्यक्रम का शुभारंभ मेजर ध्यानचंद जी की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर खेल कबड्डी, रस्साकसी, दौड़ इत्यादि खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। स्वागत उद्बोधन में जिला युवा अधिकारी श्रीमती सुषमा ने सामूहिक तौर पर खेल गतिविधियों की जानकारी से अवगत कराया। श्री कुशवाह ने कहा कि मेजर ध्यानचंद जी के त्याग दर्पण से आज खेल के क्षेत्र में प्रतिभाएं अपने प्रतिभा निखार रही है। हाकी के जादूगर के तौर पर जाने व पहचान जाने वाले हम सबके प्रेरणा स्रोत के तौर पर मेजर ध्यानचंद जी सदैव रहेंगे। इस अवसर पर उपाध्यक्ष नगर परिषद वर्षा आवलेकर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा खेल जगत के क्षेत्र में अनेकों योजनाएं के माध्यम से प्रतिभाओं में प्रतिभा निखारने का काम किया जा रहा है। उमेश पेठे ने बताया कि खेल से हम शारीरिक रूप से वह मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं।

बैतूल बनेगा खेलों का हब: केंद्रीय मंत्री श्री उईके

केंद्रीय मंत्री श्री उईके ने खेल दिवस और सांसद खेल महोत्सव के तहत रजिस्ट्रेशन का किया शुभारंभ

बैतूल (निप्र)। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनजातीय कार्य श्री दुर्गादास उईके ने जिले के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। उनके द्वारा सांसद खेल महोत्सव के तहत खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में जिले को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने बताया कि जिले में 5 करोड़ की लागत से क्रिकेट स्टेडियम जल्द बनकर तैयार होगा। इसी प्रकार जिले में ओपन ऑडिटोरियम के लिए 10 करोड़ और मल्टीपल गेम्स स्टेडियम के लिए 15 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की गई हैं। आने वाले में समय में बैतूल खेलों का हब बनेगा। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती पार्वती बाई बारस्कर, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्री हंसराज धुर्वे,श्री विकास मिश्रा, श्री प्रदीप खंडेलवाल तथा प्रभारी अपर कलेक्टर श्रीमती अनीता पटेल, एसडीएम श्री अभिजीत सिंह, जिला खेल अधिकारी श्रीमती पूजा कुरील सहित अन्य अधिकारी , स्कूली बच्चे एवं खिलाड़ी उपस्थित रहें। केंद्रीय मंत्री श्री उईके ने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति चेतना, जागरूकता और खेलों की महत्ता की दिशा में प्रेरित करने के लिए हॉकी के जादूगर श्रद्धेय श्री मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता हैं। वर्ष 2012 से प्रारंभ खेल दिवस का उद्देश्य देश के महान खिलाड़ियों के योगदान को याद करना, युवाओं में खेल भावना का विकास और राष्ट्र को खेलों के क्षेत्र में सशक्त बनाना हैं। श्री ध्यानचंद ने हॉकी के मैदान में करिश्मा दिखाकर भारत को 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाएं और भारत की खेल प्रतिभा और क्षमता से दुनिया को अवगत कराया। उन्हीं से सभी को प्रेरणा मिलती है कि जीवन में अनुशासन, समर्पण और परिश्रम से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता हैं।

भारत खेलों के क्षेत्र में नए आयाम छू रहा : केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व भारत खेलों के क्षेत्र में नए आयाम छू रहा हैं। उनका मानना है कि खेल केवल पदक तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का आधार हैं। जिसे ध्यान में रखते खेलों इंडिया प्रारंभ किया हैं, जिसमें 3 हजार से अधिक एथलीट विशेष छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट से 10 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। भारत ने खेलों में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की हैं। भारत के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक अपने नाम किए। बार्गिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 पदक जीते।

राष्ट्रीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण का मिलेगा अवसर

इस क्रम में सांसद खेल महोत्सव की परिकल्पना भी की गई है। यहां महोत्सव ग्राम, विधानसभा एवं जिला इस प्रकार तीन स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रत्येक जिले से 10 प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय खेल अकादमी में प्रशिक्षण मिलेगा। सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य नवोदित खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना, स्थानीय खिलाड़ियों को पहचान दिलाना और युवाओं को अनुशासन, फिटनेस और खेल भावना से जोड़ना हैं। केंद्रीय मंत्री श्री उइके ने कहा कि भारत का युवा खेलों के मैदान में जीतता है तो केवल पदक ही नहीं बल्कि देश के गौरव को भी बढ़ाता हैं।

खेलों से शारीरिक क्षमता वृद्धि, व्यक्तित्व विकास और चरित्र का निर्माण होता है : कलेक्टर

स्वस्थ जीवन के लिए हर आयु वर्ग में खेलों का महत्व है - कलेक्टर

सीहोर (निप्र)। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सीहोर के आवासीय खेल परिसर में अनेक खेल गतिविधियां आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर श्री बालागुरू के., एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला, जिला पंचायत सीईओ डॉ नेहा जैन और पैरालंपिक मेडलिस्ट श्री कपिल परमार ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि खेलों से जहाँ एक ओर शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है, वहीं व्यक्ति के चरित्र का निर्माण भी होता है। खेलों से महत्वपूर्ण सीख भी मिलती हैं, जो खिलाड़ी जीवन के संघर्ष, जिम्मेदारियों और कठिन परिस्थितियों पर विजय पाने में काम आती है। खेलों में भाग लेने से ऐसी खेल भावना के साथ ही साथ सकारात्मक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। खेल भावना के कारण ही हार और जीत को सहजता से लिया जाता है और परस्पर मैत्री भाव का विकास होता है। उन्होंने कहा कि आज पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी जरूरी है। विगत कुछ वर्षों से खेलों में कैरियर के अवसरों में विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए खेलों का महत्व हर आयु वर्ग में समान रूप से जरूरी है। खेल न केवल शरीर को सक्रिय बनाए रखते हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कारगर साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को शारीरिक गतिविधियों की जरूरत है। बच्चों के लिए खेल, सीखने और अनुशासन का साधन है, तो युवाओं के लिए फिटनेस और टीमवर्क की भावना का आधार है। वहीं बुजुर्गों के लिए हल्के-फुल्के खेल और व्यायाम लंबे समय तक तंदुरुस्ती बनाए रखने में मदद करते हैं। कार्यक्रम में एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला ने कहा कि आज मेजर ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि खेलों और फिटनेस के प्रति लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश के अनेक खिलाड़ियों को उनकी खेलों में अभूतपूर्व उपलब्धियों के कारण हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि सीहोर के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है।

पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मध्यप्रदेश में हो रहे स्पोर्ट्स रिवोल्यूशन का किया उल्लेख

भोपाल (नप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश की खेल उपलब्धियों को मन की बात कार्यक्रम में दो बार उल्लेख किया। उन्होंने देश के पहले खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्यप्रदेश द्वारा सबसे अधिक मेडल जीतने पर बधाई दी। साथ ही शहडोल जिले में फुटबॉल के क्रेज और उसके प्रति जर्मनी के कोच द्वारा रूचि लेने और खिलाड़ियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की भावना का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का मुरैना जिले के पिपरसेवा में श्रवण किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और स्थानीय रहवासी उपस्थित थे।

श्रीनगर की डल झील में हुआ देश का पहला वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि देश में पहला खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल श्रीनगर की डल झील में हुआ। जहाँ महिला एथलेटिस भी पीछे

नहीं रही उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया। विशेष बधाई मध्यप्रदेश को, जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते। उसके बाद हरियाणा और उड़ीसा का स्थान रहा।

शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों को जर्मनी में मिलेगा प्रशिक्षण- प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जर्मनी के फुटबॉल कोच के शहडोल जिले के फुटबॉल खिलाड़ियों से जुड़ने का प्रसंग मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों से साझा किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बताया कि एक पॉडकास्ट में उन्होंने मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में फुटबॉल के क्रेज से जुड़े एक गांव का वर्णन किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच श्री डिडमार बायर डार्फड ने सुनी।

प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा, प्रतिभा सेतु एप सहित अन्य विषयों पर की चर्चा

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सिविल सेवा परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आरंभ किए गए डिजिटल प्लेटफार्म प्रतिभा सेतु के संबंध में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने मानसून से आई प्राकृतिक आपदाओं और ऐसी स्थिति में सेना, स्थानीयजन, सामाजिक कार्यकर्ता व प्रशासन द्वारा मानवीयता के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सूरत में रहने वाले जीतेन्द्र सिंह राठौर द्वारा शहीदों की तस्वीरों के संग्रहण, सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग, इंजीनियर्स डे, विश्वकर्मा पूजा, हैदराबाद लिब्रेशन डे, लौहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कनाडा के मिसीसागार में प्रभु श्रीराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा तथा इटली के शहर कैम्प-रोतोंदो में महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा के अनावरण तथा रूस के व्लादीवोस्टोक में रामायण के अलग-अलग प्रसंगों पर बनाई गए चित्रों पर आयोजित प्रतियोगिता के संबंध में भी चर्चा की।

हाईवे की चिता सजाकर खराब सड़क का विरोध, चक्काजाम किया

शुजालपुर-आष्टा एनएच-752 पर 1 किमी लंबा जाम; एम्बुलेंस समेत कई गाड़ियां फंसीं

शुजालपुर (नप्र)। शुजालपुर के फ्रीगंज में नेशनल हाईवे-752 सी पर रविवार सुबह स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सांकेतिक अर्थी बनाकर सड़क पर ही हाईवे की चिता सजा डाली। लोगों ने गड्ढों को लेकर विलाप किया और सरकार-प्रशासन की बेरुखी पर गुस्सा जताया।

रहवासियों ने सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग

की। लोगों ने कहा कि गड्ढों में गिरकर कई लोग घायल हो चुके हैं। हादसे का शिकार बन चुके लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। करीब 1 घंटे तक चले इस विरोध प्रदर्शन के चलते एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 35 मरीजों और बुजुर्गों को लेकर नेत्र शिविर जा रही एम्बुलेंस भी आधे घंटे तक जाम में फंसी रही। हाईवे से लगे फ्रीगंज क्षेत्र में कई जगहों पर बड़े गड्ढे स्थानीय लोगों का कहना है कि आष्टा से पचोर को जोड़ने वाले इस हाईवे से लगे फ्रीगंज इलाके में कई जगहों पर बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों में पानी भर जाता है। सड़क किनारे स्थित गणेश पंडालों तक गाड़ियों के पहियों से कीचड़ उछलकर पहुंच रहा है।

महेश्वर में गूंजा, 'आला रे आला सचिन आला'

क्रिकेटर तेंदुलकर पत्नी-बेटी के साथ यात्रा पर पहुंचे; फैंस एक नजर देखने को उमड़े

महेश्वर (नप्र)। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पत्नी अंजलि और बेटी सारा के साथ दो दिन की निजी यात्रा पर महेश्वर पहुंचे। उन्हें देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा थे। उन्हें देखते ही क्रिकेट प्रेमियों ने 'आला रे आला सचिन आला' और 'भारत का रत्न कैसा हो, सचिन जैसा हो' जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रशंसक उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाने और सेल्फी लेने के

लिए बेताब दिखे। सचिन ने भी सहजता दिखाते हुए कुछ देर तक लोगों के साथ फोटो खिंचवाई, लेकिन बढ़ती भीड़ के कारण उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। सचिन पत्नी डॉ. अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ महेश्वर के अहिल्या फोर्ट हेरिटेज होटल में ठहरे हैं। वे महेश्वर और आसपास के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। उनके कार्यक्रम में महारानी अहिल्याबाई का महल और किला, नर्मदा आरती और भगवान काशी विश्वनाथ और राजराजेश्वर मंदिर के दर्शन भी शामिल हैं।

भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में चर्चा

'स्व' की खोज से ही मिलती है असली स्वाधीनता, सिर्फ स्वतंत्रता से नहीं

भोपाल (नप्र)। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में आयोजित अध्ययन समूह की मासिक श्रृंखला में छात्रों और शिक्षकों ने 'स्व से साक्षात्कार' पुस्तक पर विचार साझा किए। परिचर्चा का केंद्र स्वाधीनता और स्वतंत्रता का अंतर और 'स्व' की असली पहचान रहा।

यह प्रज्ञा प्रवाह अंतर्गत संचालित अध्ययन समूह की 11वीं मासिक बैठक थी। इसमें अरुण कुमार ने लिखित 'स्व से साक्षात्कार' पुस्तक के अध्याय 'स्वत्व के लिए संघर्ष' का वाचन किया। उन्होंने कहा कि हम 'इंडिया' कहते हैं, अपनत्व की भावना कम होती है, लेकिन 'भारत' कहने में ज्यादा आत्मीयता महसूस होती है। यही 'स्व' की असली पहचान है।

क्रांतिकारियों का संघर्ष इसी स्व के लिए

चर्चा में यह बात प्रमुखता से उभरी कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता में मूलभूत अंतर है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधनों से मुक्ति है, जबकि स्वाधीनता का मतलब है अपने मूल्यों, आत्मा और संस्कृति के अनुरूप जीवन जीना। वक्ताओं ने कहा कि यही सोच भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बनी। आंदोलन की प्रेरणा स्व त्रयी स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज से मिली। खासकर बंगाल के क्रांतिकारियों का संघर्ष इसी स्व के लिए बड़ी भूमिका निभाता रहा।